20 जून, 2023 * वर्ष 32, पृष्ठ संख्या 60, अंक-6

राजस्थान सुजस

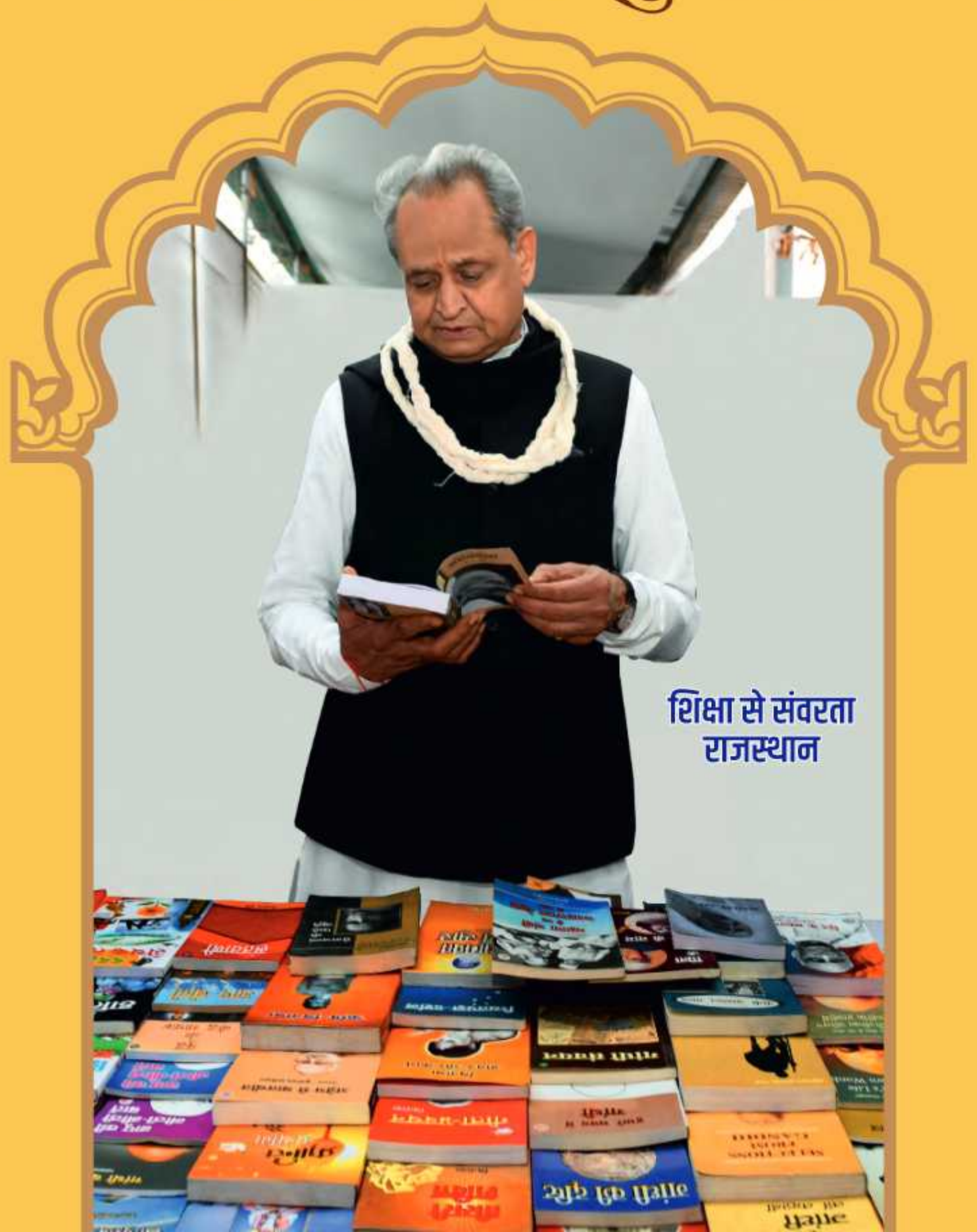

शिक्षा से संवरता राजस्थान

मोलेला के मृण शिल्पकार

राजसमंद जिले की खमनोर तहसील में स्थित मोलेला गांव के मृण शिल्पकार लोक देवी-देवताओं का माटी में रूपांकन करते हैं। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। मोलेला में मिट्टी की फड़ व मांदल नामक वाद्य यंत्र का निर्माण भी होता है। बदलते परिवेश में कलाकारों ने आधुनिक कलाकृतियां गढ़ना शुरू कर दिया है। मोलेला गांव के शिल्पकार देश-दुनिया में कला की छाप छोड़ चुके हैं। इन्हें पद्मश्री सहित अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इस गांव में शीघ्र ही शिल्पग्राम (शिल्पबाड़ी) की स्थापना होगी। शिल्पबाड़ी में सेमिनार हॉल, प्रदर्शनी हॉल, कैफेटेरिया व अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से मोलेला के शिल्पकर्मी अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर बिक्री कर सकेंगे।

आलेख और छाया: भारत मीणा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 32 अंक 06

जून, 2023

इस अंक में

लोक जीवन	2
संपादकीय	4
नवाचारों से बदलता शिक्षा का परिदृश्य	5
Rajiv Gandhi Scholarship	11
बातचीत	12
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	16
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना	18
निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना	19
राजस्थान की गौरवमयी गाथा	20
चिकित्सा शिक्षा	22
ज्ञान संकल्प पोर्टल	24
उच्च शिक्षा	26
इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार	29
बालिका शिक्षा	32
नो बैग डे	36
नवाचारों से संवर रहा भविष्य	39
भामाशाह शिक्षक	42
राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय	44
सामयिकी	47
महंगाई राहत कैंप	54
66वें नेशनल स्कूल गेम्स	56
कृषि शिक्षा	58
धरोहर	59
तब और अब	60

साक्षात्कार 8

स्मार्ट क्लास 14

फोटो फीचर 30

प्रधान संपादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

सहायक संपादक
महेश पारीक

आवरण छाया
सूजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 98292-71189, 94136-24352
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।
कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा

"सा विद्या या विमुक्तये" यानी शिक्षा वह है जो बंधनों से मुक्त करती है। यह हमारी सोच का विस्तार करती है और हमारा सर्वांगीण विकास करने में मदद करती है। इससे हम जीवन को खुशहाल और सार्थक बना सकते हैं। जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा से हमें सही-गलत के भेद का पता चलता है। इसकी मदद से हम जीवन की बड़ी मुश्किलों का सामना कुशलता से कर सकते हैं। जीविकोपार्जन के लिए भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में वे ही राष्ट्र ताकतवर की श्रेणी में हैं जिनके पास ज्ञान की शक्ति है।

बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने, इसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और योग्य शिक्षक तैयार करने के लिए राज्य सरकार अनेक स्तर पर प्रयास कर रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 युवाओं को विदेशों में नि:शुल्क पढ़ने का अवसर मिल रहा है। अनुप्रति योजना के माध्यम से 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग करवाई जा रही है। हर शनिवार को नो बैग डे जैसे नवाचारों से शिक्षा में रचनात्मकता का विस्तार हो रहा है। ई-एजुकेशन के महत्व को देखते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और बच्चों के पोषण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जैसी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं संचालित हैं।

इन समग्र प्रयासों की वजह से ही प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में आशाजनक सफलता प्राप्त की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भी प्रदेश ने वन प्लस रैंकिंग हासिल की है।

शिक्षा के विविध आयामों को समेटे राजस्थान सुजस का जून, 2023 का यह शिक्षा विशेषांक अभिवादन एवं शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत है।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

नवाचारों से बदलता शिक्षा का परिदृश्य

■ डॉ. मोहनलाल यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा

देश व समाज की प्रगति और विकास के लिए शिक्षा सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सार्थक पहल और प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी बदौलत स्कूली शिक्षा में राजस्थान ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी अनूठी पहचान बनाई है। बीते कुछ समय में प्रदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 66 हजार 500 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 94 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक कल्याण, शैक्षिक सुधार और विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के सृजन की सतत मुहिम से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शैक्षिक सरोकारों और बेहतरीन नवाचारों से प्रदेश में राज्य सरकार के शिक्षा के विस्तार की परिकल्पना को न सिर्फ पूर्ण साकार किया है बल्कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 1+ (वन प्लस) रैंकिंग हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा का श्रेष्ठ उदाहरण भी पेश किया है।

प्रदेश में शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला और शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती जाहिदा खान के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक और गुणात्मक सुधार के कार्य हो रहे हैं। विभाग का एक ही ध्येय है कि प्रदेश के हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता और समान अवसरों से युक्त शिक्षा प्रणाली का पूरा लाभ मिले। इस लक्ष्य की दिशा में ऐसे कई नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो प्रदेश की शिक्षा के बदलते परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। कमजोर, वंचित और कम आर्थिक संसाधनों वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर वर्ष 2019 में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) का संचालन शुरू किया गया। इन विद्यालयों की अपार सफलता के बाद प्रदेशभर में अब तक 2,753 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर इन विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। सरकारी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचारों को लागू करने में राजस्थान वर्तमान में उत्तरी भारत में एकमात्र

राज्य है। राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में किया जा रहा है। ऐसे में राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आने वाले विद्यार्थी, जो निजी स्कूलों की मोटी फीस वहन करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय न केवल एक उत्कृष्ट विकल्प बनकर उभरे हैं, बल्कि उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

राजस्थान में शिक्षा विभाग कई फ्लैगशिप योजनाओं का भी संचालन कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विभाग समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, गुणवत्ता को बढ़ाने और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक लगभग 67 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी विभाग की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को हर शैक्षणिक दिवस पर दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से 68.22 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

स्मार्ट कक्षाओं का संचालन

ई-एजुकेशन की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन की शुरुआत कर नई पहल की गई है। विभाग द्वारा प्रदेश के चिन्हित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न चरणों में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं तथा शेष विद्यालयों में लैब स्थापना का कार्य जारी है। विद्यालय में शैक्षिक प्रगति और गतिविधियों की अनवरत मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करते हुए 'शाला संबलन एप' का निर्माण किया गया है। अब इस एप के माध्यम से कम समय में सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक किया जा रहा है।

कोरोना महामारी में स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट 'स्माइल' तथा 'आओ घर में सीखें' अभियान के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखी गई है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत एक तिहाई छात्र, जिनके पास इंटरनेट व स्मार्टफोन की सुविधा थी, उन्हें 'व्हाट्सएप' तथा 'यूट्यूब' आदि डिजिटल माध्यमों के जरिए शिक्षा से जोड़ा गया।

शिक्षकों द्वारा 'स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप' के माध्यम से प्रतिदिन अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई। साथ ही ई-कक्षा के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों के वीडियो बनाकर यूट्यूब तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए। इन वीडियो को अध्यापकों द्वारा 'व्हाट्सएप ग्रुप' पर शेयर किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यार्थी डिजिटल माध्यम की सुविधाओं से वंचित थे। इन विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं, 'होम विजिट्स' तथा फोन वार्ता के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा गया। साथ ही दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से भी पाठ्य सामग्री इन विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई।

हवामहल कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बनाए रखने के लिए आनंददायक माहौल में कहानियों द्वारा अध्ययन कराया गया। यहीं नही मूकबधिर एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग ने 'मिशन समर्थ' के इनिसिएटिव के तहत 'साइन लैंग्वेज' में वीडियो कंटेंट बनाकर इन विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग निरंतर गम्भीर प्रयास कर रहा है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, शिक्षण सामग्री एवं सुरक्षित आवास की सुविधाओं से युक्त 316 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का प्रदेश में सफल संचालन किया जा रहा है, जिनमें 43 हजार से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं। राजस्थान में बालिका शिक्षा के बढ़ते स्तर में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

बच्चों में रोजगारोन्मुखी प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का संचालन प्रारंभ किया गया। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किसी निश्चित क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए तैयार करती है ताकि उनको स्कूली शिक्षा के बाद सीधे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। प्रदेश में 33 जिलों के 1680 राजकीय विद्यालयों में 15 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिनमें लगभग 2 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभाग द्वारा और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश में 9वीं क्लास से एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल की शुरुआत करके विद्यार्थियों की समस्याओं का सिर्फ समाधान किया बल्कि रोजगार संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शैक्षणिक गतिविधियों में जनसमुदाय की भागीदारी के लिए सामुदायिक बाल सभाओं के आयोजन को देश भर से सराहना प्राप्त हुई। हर शनिवार को 'नो बैग डे' जैसे नवाचारों ने बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ रचनात्मकता व सृजनात्मकता को बढ़ाने का काम किया है। रचनात्मक और नवीन शिक्षण विधि से होमवर्क के लिए 'एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग' (एबीएल) किट्स तथा 'स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम' के द्वारा बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं बालिकाओं की सुरक्षा पर फोकस करते हुए प्रदेश की करीब 29 लाख छात्राओं में आत्मविश्वास का संचार कर उन्हें निडर बनाने के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सरकारी स्कूलों की बदल रही तस्वीर

राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब बदलने लगी है। शैक्षिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं तथा भौतिक संरचना में निजी स्कूलों से राजकीय विद्यालय आज पूर्ण प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए भामाशाह भी आगे आए हैं।

शिक्षा विभाग का ज्ञान संकल्प पोर्टल राजकीय विद्यालयों के कायाकल्प के इस अभियान में एक प्रभावी वित्त पोषक पोर्टल की भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से समाज के दानदाता एवं भामाशाह राजकीय विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को बदलने में योगदान दे रहे हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल के जरिए लोगों को विद्यालयों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई हैं। इसके परिणाम धरातल पर प्रतिफलित हो रहे हैं।

राजस्थान का शिक्षा विभाग प्रदेश के नौनिहालों के सपनों को साकार करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। बालक-बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में प्रदेश ने शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में आशाजनक सफलताएं प्राप्त की हैं। राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य गुणवत्ता और नवाचारों की दिशा तय करने में देश में एक आदर्श स्थापित कर रहा है।

सरकार का क्वालिटी एजुकेशन पर पूरा फोकस

मिल रहे हैं सकारात्मक नतीजे

राजस्थान ने स्कूली शिक्षा में एक के बाद एक लीक से हटकर कार्य करते हुए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम बने हैं। स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के प्रदर्शन के मानक हो या शैक्षिक नवाचार, राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों को गति देने की बात हो या फिर कई ऐतिहासिक उपलब्धियों ने राज्य को नई पहचान दी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हुए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ महीनों में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक के बाद एक कई विशिष्ट कीर्तिमान भी बनाए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 'नॉलेज सेंटर' के रूप में विकसित करने के लिए 'उत्कृष्टता प्रबंधन' की दिशा में अनवरत प्रयास जारी है।

डॉ. बी. डी. कल्ला, शिक्षा मंत्री, राजस्थान का मनमोहन हर्ष, उप निदेशक (जनसंपर्क), द्वारा लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख अंश।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियां को आप किस प्रकार देखते हैं?

मुझे 'राजस्थान सुजस' के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह बताते हुए खुशी है कि वर्तमान में राजस्थान, शैक्षिक विकास की दृष्टि से देश के तीन अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालयों में नवाचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुयोग्य नागरिक बनाते हुए शैक्षणिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। नीति आयोग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 'परफोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' में वर्ष 2021-22 में राजस्थान उत्कृष्ट श्रेणी में रहा। सम्पूर्ण भारत में 733 जिलों के बीच हमारे सीकर जिले ने देश में प्रथम, झुंझुनूं ने द्वितीय एवं जयपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार वर्ष 2012 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी कक्षा और विषयवार औसत अंकों के आधार पर हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन राज्यों में रहा। वहीं भारत सरकार की इंस्पायर अवॉर्ड मानक योजना में सत्र 2022-23 में ऑनलाइन नॉमिनेशन में एक लाख 65 हजार 825 नॉमिनेशन के साथ लगातार तीसरे वर्ष राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश गत दो वर्ष से प्रथम स्थान पर है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार (सत्र 2021-22) में राज्य के दो राजकीय विद्यालयों स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़, टोंक एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, भीलवाड़ा का चयन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इन विशिष्ट उपलब्धियों के साथ हमने गत कुछ माह में नवाचारों के दम पर पांच विश्व कीर्तिमान भी बनाए हैं।

ये विश्व कीर्तिमान कौन-कौन सी गतिविधियों और नवाचारों से संबंधित हैं?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से कोरोनाकाल में जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स तैयार कर उसके माध्यम से पढ़ाई कराई गई। लर्निंग गैप्स की पूर्ति के लिए 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को कॉम्पेटेंसी बेस्ड वर्कबुक से शिक्षण द्वारा कक्षास्तर तक लाने की पहल की गई। इसके बाद राज्य स्तरीय कॉमन पेपर से मूल्यांकन कर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया गया। इसमें राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के 65 हजार विद्यालयों के लगभग 45 लाख विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल्स की जांच के लिए 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआई) के माध्यम से किया गया। एआई के प्रयोग से इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का त्वरित मूल्यांकन कर स्कूल शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान बनाया। राजस्थान के सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत गत वर्ष 12 अगस्त को प्रातः 10.15 बजे से 10.40 बजे तक एक साथ पांच देशभक्ति गीत गाए। इसमें सभी 33 जिलों में कक्षा 1 से 12 के एक करोड़ 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया। गत साल महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राज्य के एक करोड़ 47 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 'नो-बैग-डे' के नवाचार के तहत हमने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर, 2022) से राज्य के स्कूलों में 'चेस इन स्कूल एक्टिविटी' का आगाज किया। इस दिन राज्य में एक साथ 38 लाख 21 हजार 9 विद्यार्थियों ने 'चेस इन स्कूल एक्टिविटी' में भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया।

इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जंबूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी को रोहट (पाली) में किया गया। इसमें देशभर व दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से लगभग 35 हजार स्काउट्स व गाइड्स ने भाग लिया। राज्य में 67 वर्ष बाद जंबूरी के इस आयोजन में 'टेम्प्रेरी स्टेडियम निर्माण' का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। हमारे इन सभी कीर्तिमानों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।

शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों और नए विद्यालय आरंभ करने की दिशा क्या रही है और आगे की क्या योजना है?

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को विगत चार वर्षों में 81,885 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं और अभी 90,399 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं साथ ही विभिन्न संवर्गों में 50,169 पदोन्नति प्रदान की गई हैं। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जबकि 1,779 विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर, 1,195 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक, 4,446 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं 1,470 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। इसी प्रकार राज्य में बालिकाओं को प्रोत्साहन और बालिका शिक्षा की पहुंच गांव-ढाणी तक सुनिश्चित करने के लिए 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक, 400 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 480 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार' सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के विद्यालयों में बालिकाओं की क्षमता संवर्धन के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 2.50 लाख छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। बालिकाएं अब शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों को ही देख लीजिए, हर वर्ष हमारी बेटियां अव्वल प्रदर्शन कर रही हैं। यह प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और जनता के लिए बड़ी सुखद अनुभूति है।

प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल आरम्भ किए हैं, इस नवाचार की प्रगति और आगे की प्लानिंग क्या है?

राज्य सरकार ने मौजूदा कार्यकाल में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में नवाचार की विशेष पहल की है। यह प्रदेश के शैक्षणिक विकास एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का नया पत्थर है। हम प्रदेश में अब तक 2,700 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ कर चुके हैं। आगामी दिनों में प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की है कि जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी सरकार प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ करेगी। प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से भी बेहतर हों, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। प्रदेश में शिक्षण गतिविधियों को नए आयाम देने के लिए राजकीय इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालय के साथ ही स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश, एडमिनिस्ट्रेशन एवं लीडरशिप डेवलपमेंट की विशेष ट्रेनिंग देने की दिशा में भी विभाग कार्य कर रहा है। प्रदेश के इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू की गईं। इसके प्रति अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का अच्छा रुझान सामने आया है। अभिभावकों ने इन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में विशेष उत्साह दिखाया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तो 30 सीटों पर प्रवेश के लिए 2,600 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश में वर्तमान में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अध्ययनरत हैं। इस संबंध में एक और विशिष्ट तथ्य यह है कि राज्य के 1,033 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने के साथ ही राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू की गईं। ऐसा करने वाला राजस्थान उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है। इसके साथ ही हम अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रदेश में किस प्रकार की तैयारी है?

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 का नया शैक्षणिक मॉडल तैयार करते हुए कई परिवर्तन किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव एवं जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित कर दी गई हैं।

आपने पिछले दिनों राइट टू एजुकेशन (आरटीई) की लॉटरी निकाली थी, प्रदेश में इस एक्ट के लागू होने के बाद गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को कैसा फायदा मिला है?

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जो कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेश में वर्ष 2012-2013 से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है। तब से लेकर अब तक राज्य के करीब 9 लाख बालक-बालिकाओं को इसका सीधा फायदा मिला है। आरटीई के तहत राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शिता के साथ समस्त प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार निजी विद्यालयों को इन विशेष वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए राशि का पुनर्भरण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आरटीई के तहत जो निजी विद्यालय सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता और तत्परता से समय पर फीस का पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।

आरटीई को लेकर अभिभावकों के कई प्रकरण सामने आते हैं। उनके समाधान के लिए विभागीय स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है?

आरटीई की लॉटरी के बाद जारी प्रक्रिया में प्रदेश में कहीं भी अभिभावकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए अधिकारियों को उनकी समस्याओं और प्रकरणों के संबंध में त्वरित निर्णय लेकर तत्परता से समाधान के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। आरटीई की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि

अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वे वाट्सएप नंबर 7014812375 एवं 7014878012 पर शिकायत के बारे में अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर शिकायत मिलने के बाद परिषद के स्तर पर अधिकारियों की समिति नियमानुसार जांच एवं परीक्षण कर इसका समयबद्ध निस्तारण करती है। इन व्हाट्सएप नंबर के अलावा हेल्पलाइन नंबर 0141-2719073 एवं 0151-222140 पर आरटीई के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संपर्क किया जा सकता है।

पीएम श्री योजना में 402 सरकारी विद्यालयों के चयन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्राथमिक शिक्षा के 56 सरकारी स्कूल शामिल हैं। प्रदेश के कुल 718 स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें से राजस्थान ने पहले चरण में ही 56 प्रतिशत विद्यालयों का चयन कराते हुए विशेष सफलता प्राप्त की है। जुलाई माह में द्वितीय चरण में शेष स्कूलों का चयन प्रस्तावित है। यह राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना, नामांकन में उत्तरोत्तर प्रगति, विद्यालयों के ढांचागत विकास एवं शैक्षिक नवाचारों की पहल और टीम स्कूल एजुकेशन राजस्थान के सतत प्रयासों से सामने आया एक और सुखद परिणाम है।

मैं इसके लिए हमारे शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मियों की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 3 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ था। इस पर आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक स्क्रूटनी में प्रदेश के बेंचमार्क सरकारी स्कूलों (21 हजार 356) की ओर से आवेदन कराने में राजस्थान देश में अव्वल रहा। इतना ही नहीं ऑनलाइन आवेदन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने 13 हजार 931 सरकारी स्कूलों का सत्यापन कराते हुए देश के अन्य बड़े राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के 7,892, आसाम के 7,776, उत्तर प्रदेश के 7,054, महाराष्ट्र के 4,848, कर्नाटक के 4,700, पंजाब के 4,632, मध्य प्रदेश के 3,483, गुजरात के 2,163 तथा उत्तराखंड के 1,704 स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन के बाद वैरीफाइड किया गया।

पीएम श्री योजना में चयन के लिए बेंचमार्क में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा?

इस योजना के सरकारी स्कूलों के चयन के लिए जो बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं, उनमें एलीमेंट्री सेटअप (कक्षा 1 से 5 एवं 1 से 8 तक) तथा सेकंडरी सेटअप (कक्षा 6 से 12 तक) में स्कूलों में नामांकन राज्य के औसत नामांकन से अधिक, अच्छी कंडीशन में विद्यालयों का पक्का भवन, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए अलग से सुविधा, सभी शिक्षकों के पास गाइडलाइन के अनुरूप आईडी कार्ड, बैरियर फ्री एक्सेस रैम्प, सुरक्षा पर फोकस, विद्युत कनेक्शन, लाइब्रेरी एवं खेलकूद गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इनमें राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति को योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक स्क्रूटनी में (21 हजार 356 स्कूल), प्रथम चरण में (402 स्कूल) और कुल चयन (718 स्कूल) अव्वल आंके गये हैं, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

प्रदेश के शैक्षणिक विकास और प्रगति में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों (एसडीएमसी) की क्या भूमिका है?

प्रदेश के स्कूलों के विकास एवं संवर्धन में एसएमसी एवं एसडीएमसी प्रमुख धुरी हैं। ये समितियां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश में शैक्षिक नवाचारों की संवाहक बन सकती हैं। विद्यालयों में एसएमसी एवं एसडीएमसी की स्थापना और सर्वश्रेष्ठ समितियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की योजना के तहत प्रत्येक साल हर जिले से श्रेष्ठ समितियों का चयन कर विभाग द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाता। पिछले दिनों एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी जिलों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एसएमसी एवं एसडीएमसी के चयन के बाद उनको पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में कार्यरत एसएमसी एवं एसडीएमसी के सदस्यों से मेरी अपील है कि वे विद्यालय विकास से संबंधित चारदीवारी, कक्षा-कक्ष, लैब एवं वाचनालय निर्माण जैसे विस्तार कार्यों के लिए आगामी 25 सालों का मास्टर प्लान बनाएं और शैक्षिक विकास से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रभावी सुपरविजन भी करें।

राजस्थान सुजस के शिक्षा पर केंद्रित इस विशेष अंक के माध्यम से आप प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 'जॉयफुल एजुकेशन' और 'लर्निंग प्रोसेस' के संवर्द्धन के लिए सतत प्रयास कर रही है। अब 'परफेक्ट कॉम्पीटिशन' और 'द बेस्ट' का युग है। विद्यार्थी जितनी अधिक मेहनत करते हैं, उतना ही कॅरियर में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को कॅरियर में लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए मैं विशेष तौर पर यह अपील करना चाहता हूं कि वे 'अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हैल्दी-वेल्दी एंड वाइज' के मूल-मंत्र को आत्मसात करें। सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करने वाले जीवन में बुद्धिमान और सफल होते हैं। वे आयु, बुद्धि, बल, धन और यश में वृद्धि के लिए सदैव अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करने का संकल्प लें। विद्यार्थियों को कौए की तरह चेष्टाशील, बगुले की भांति एकाग्र एवं श्वान की तरह जाग निद्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। वे जंक फूड के स्थान पर पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें और अल्पाहार के नियमों को भी अपनाएं।

मैं सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूं कि हमारे शिक्षक सदैव प्रदेश में शैक्षिक क्रांति के शिल्पकार रहे हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की सतत पहल, प्रयास और शैक्षिक नवाचारों से प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के स्तर में लगातार गुणात्मक सुधार हो रहा है। सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित टीचर और तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसे में मेरी सभी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों से अपील है कि वे सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाने के संकल्प के साथ कार्य करें। हमें निजी स्कूलों से 'हेल्दी कॉम्पीटिशन' के लिए 'इफेक्टिव सुपरविजन' और 'प्रबंधकीय कौशल' के मूल मंत्र के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण प्रदेश के सरकारी स्कूलों के स्तर को नए मुकाम पर ले जाने के लिए और अधिक सजगता और समर्पण के साथ अपना सतत योगदान जारी रखेंगे।

Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence

Realising Dream of Studying Abroad

■ Rakshita Yadav
APRO

All parents dream of providing quality education to their children but unfortunately even the talented and distinguished students from middle and lower income groups are not able to meet the financial requisites of international studies.

Acknowledging the fact that every student deserves an equal opportunity to exhibit his/her talent and with the determination and commitment of Chief Minister Shri Ashok Gehlot, Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence scheme has been initiated. This idea of Rajasthan government was built on the foundation of modernisation and expansion of education for every student of Rajasthan.

The scheme was launched in the year 2021-22 by the Department of Higher Education with the objective to provide assistance to such students who are native of Rajasthan and selected for pursuing higher studies abroad for undergraduate, postgraduate and post-doctoral research work in a university listed in the latest QS global ranking. Apart from this, the purpose of this scheme is to motivate the students of the state to study abroad and to help them in making a career and to motivate such students to participate in the progress of the state. It is being undertaken as a medium to inspire the youth of the state and catalyse personal, social and economic development.

Students belonging to middle and lower income groups are eligible to get scholarships under this scheme. Preference for the scholarship will be given to the students of low income groups. Students wishing to avail the benefits can apply through SSO ID.

Standing firm on his decision to provide support to as many students as possible, Chief Minister Shri Ashok Gehlot in his Budget announcement of the year 2023-24 has increased the number of students for scholarship from 200 to 500. Over the last year a total of 249 students have been selected for the scholarship to study in international universities.

Harsh is studying in the University of Toronto

The scheme has worked as an impetus in the inspirational journey of many students of Rajasthan like Harsh Pareek who belongs to a small town in Jhunjhunu. He belongs to a middle class family and has been a meritorious student throughout his schooling. But because of financial constraints he was not able to pursue his dream of becoming a data science engineer. When he got to know about this scheme, he said that he was on cloud nine. He immediately registered himself under the scheme and now he is studying mathematics and statistics in the University of Toronto and aspires to work in the field of Artificial intelligence. Harsh said that his college fees of two semesters along with a part of living expenses has been reimbursed. Till now he only dreamt of going abroad to study but the Rajasthan government has made it possible for many students like Harsh to reach their goals.

Similarly a very bright student named Anshika Kalra belonging to a middle class family from Jaipur got the opportunity to study English literature in the University of British Columbia. She said that she was on the top of the world when she got to know about this scheme and she was then able to see her dreams coming to reality. She also said that under this scheme she received the full amount of her tuition fee which was around 15 lakhs and a portion of living expenses. She said that this has come as a huge support to her career.

Likewise Kusum Choudhary, native of Jodhpur who is now studying letters and science in the University of Maryland in the US, said that her father is a landless farmer and sometimes she and her siblings also helped her father in the field. With this income they were barely able to meet the basic needs of life. She has been a meritorious student but in such a situation it was difficult for her to even think of going abroad to study. Meanwhile, she came to know about this scholarship scheme and got herself registered. Expressing her gratitude, she said that this financial aid by the government has been very important to her career and she feels lucky to get this opportunity. She said it has given her wings that she never even dreamt of.

Kusum is studying in the University of Maryland

Rajiv Gandhi scholarship scheme for academic excellence has allowed the students to move towards a much evolved life and enhanced the performance of students on various metrics. The scheme has worked wonders for students.

नए सत्र में स्मार्ट क्लास रूम

टीचिंग और बालिका सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य में स्कूली शिक्षा माहौल में सकारात्मक सुधारों से बदलते परिदृश्य के बीच शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र में कई नवाचारों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की उपलब्धियों को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग स्कूली विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण क्लास रूम, टीचिंग, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या व समयावधि को कम करते हुए कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन का समय बढ़ाने और बालिका सुरक्षा के लिए सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य कर रहा है।

श्री नवीन जैन, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग से मनमोहन हर्ष, उप निदेशक (जनसंपर्क) से हुई बातचीत के प्रमुख अंश:

स्कूल शिक्षा विभाग में नए शैक्षणिक सत्र में क्लास रूम टीचिंग और शिक्षक-प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को लेकर क्या विशेष प्लानिंग है?

स्कूल शिक्षा में शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अपना महत्व है। कई ऐसे प्रशिक्षण हैं, जिनकी थीम, प्रकृति और उद्देश्य समान हैं। ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों को व्यावहारिक बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों की संख्या, समयावधि और टाइमलाइन की समीक्षा कर ऐसा कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिससे इनमें उपयोग में लिए जाने वाले दिनों की संख्या कम हो और इस बचे हुए समय का सदुपयोग कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन को प्रभावी बनाने में होगा। कुछ प्रशिक्षण या अभियान ऐसे हैं, जो स्कूलों में विद्यार्थियों के व्यापक हित में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित होते हैं। नए शैक्षणिक सत्र में ऐसे कार्यक्रमों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए इन विभागों के समन्वय से साझा अभियान भी चलाए जाएंगे। विभाग में टीचर्स की ट्रेनिंग कार्यक्रमों में लगने वाले मानव श्रम, समय और खर्च को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 'ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स' के वीडियो तैयार कर उन्हें 'यूट्यूब' पर अपलोड करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को अपने स्कूल मुख्यालय से बसों में सफर कर अन्यत्र जाना पड़ता है, इसमें समय भी जाया होता है और उन्हें अनावश्यक परेशानी भी होती है। ऐसे प्रशिक्षणों के वीडियोज 'इनहाउस' तैयार कर 'यूट्यूब' पर डाले जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक इनको फिर से देख सकेंगे, इन्हें विद्यार्थियों को भी दिखाया जा सकता है और अभिभावक भी 'यूट्यूब' पर इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियोज विभाग की परमानेंट एसेट बन जाएंगे और इससे 'टीचर्स ट्रेनिंग' की 'फ्रिक्वेंसी' को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हम नए सत्र से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कॅरियर काउंसलिंग के लिए 'डायल फ्यूचर' नाम से भी एक इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।

यह 'डायल फ्यूचर' किस प्रकार का कार्यक्रम है, इसके जरिए बच्चों को किस प्रकार मार्गदर्शन दिया जाएगा?

इस इनिशिएटिव के तहत प्रदेश में कक्षा दसवीं में उत्तीर्ण होने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों के स्तर पर संकाय चयन और कॅरियर के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक-एक शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाएंगे। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आरएससीईआरटी), उदयपुर एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा इसके लिए मॉडयूल निर्माण, पथ प्रदर्शक शिक्षकों के चयन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाने, मार्गदर्शन के लिए ब्रोशर तैयार करने, राज्य एवं जोन स्तर पर हेल्प डेस्क गठित करने और पथ प्रदर्शकों के लिए आमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन जैसी गतिविधियां टाइमबाउंड कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है। 'डायल फ्यूचर' कार्यक्रम में पथ प्रदर्शक के रूप में चयनित शिक्षकों द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों में सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में संस्था प्रधानों द्वारा 28 जून से 5 जुलाई तक विद्यार्थियों को 'डायल फ्यूचर' (भविष्य की राह) परामर्श कार्यक्रम के तहत मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को देखा जाए तो छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में लगातार बेहतर रहता है, बालिका शिक्षा और विशेषकर बालिका सुरक्षा को लेकर विभाग की कार्य योजना क्या है?

बोर्ड की परीक्षाओं में ओवरआल रिजल्ट के साथ ही कई अन्य पैरामीटर्स पर बालिकाओं का निरंतर अच्छा प्रदर्शन खुशी की बात है। यह इस बात का भी परिचायक है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और विभाग के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। जहां तक बालिका सुरक्षा का सवाल है, यह हमारे विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विभाग में इस संवेदनशील विषय पर आने वाले दिनों में जोर-शोर से कार्य किया जाएगा। आगामी अगस्त से दिसंबर माह के बीच सभी स्कूलों में बालिकाओं को 'गुड-टच' और 'बैड-टच' का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए टीचर्स का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा रहा है। इसके अलावा नए सत्र में 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' के लिए छात्राओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बाद श्रेष्ठ बालिकाओं के बीच राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने की भी योजना है।

स्मार्ट क्लासेज के कॉन्सेप्ट पर विभाग कैसे कार्य कर रहा है?

शिक्षा विभाग में ऐसे स्कूल जहां सब्जेक्ट टीचर्स पदस्थापित नहीं हैं, वहां सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करते हुए 'आईसीटी लैब' स्थापित की गई हैं। नए सत्र में ऐसे चिह्नित स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट क्लासेज का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट टीवी और हार्ड ड्राइव में टीचिंग-लर्निंग मेटेरियल विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। हार्ड ड्राइव में प्री लोडेड लर्निंग मेटेरियल पाठ्यक्रम के अनुरूप संचित कर विद्यालयों में भेजा जाएगा। इससे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां इंटरनेट की गति कम रहती है, वहां भी ऑफलाइन मोड में छात्र-छात्राएं आईसीटी क्लासेज का लाभ उठा सकेंगे। अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में हार्ड ड्राइव और उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार टीचिंग-लर्निंग मेटेरियल लोड कर विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी स्कूलों में साप्ताहिक समय सारणी बनाकर इसे अमल में लाया जाएगा। यह कार्य जुलाई के तीसरे सप्ताह से आरंभ होगा।

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की मौजूदा स्थिति और इसमें आगामी कार्य योजना क्या है?

प्रदेश में वर्ष 2015 में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम 70 राजकीय विद्यालयों में प्रारंभ किया गया था, जो 2022-23 में लगभग 2,000 विद्यालयों तक पहुंच चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को विभिन्न व्यवसायों एवं जॉब रोल्स का प्रशिक्षण देने के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। विभाग ने नए सत्र के दौरान प्रदेश में गत वर्ष जिन जिलों के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनमें रेंडम आधार पर कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों के कौशल की जांच के लिए 'थर्ड पार्टी एसेसमेंट' कराएंगे। कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम विभाग में ही रिसोर्स पर्सन तैयार करेंगे, जो फील्ड में जाकर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का आकलन करेंगे। इससे प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को नई दिशा देने में मदद मिलेगी। साथ ही फील्ड में इस संबंध में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का भी मार्ग प्रशस्त होगा। व्यावसायिक शिक्षा में राज्य के जिलों की परिस्थितियों तथा इंडस्ट्रीज की मांग के अनुसार नए कोर्स भी प्रारंभ करते हुए नये सत्र में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस फील्ड में अच्छा अनुभव रखने वाले 'ट्रेनिंग पार्टनर्स' के साथ कार्य किया जाएगा।

राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं में विस्तार के लिए निर्माण कार्य कराए जाते हैं। विभाग द्वारा इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनको पूरा करने के लिए क्या प्रयास होते हैं?

सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए 'डिजिटल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म' के तहत एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर से निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्क्स की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति और वर्क ऑर्डर जारी करने की रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग होगी। वहीं फील्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति एवं उनके पूर्ण होने पर भुगतान से स्टेज के बारे में त्वरित फीडबैक मिलेगा। यह निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी मददगार होगा।

स्कूल शिक्षा के साथ ही आपके पास भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की भी जिम्मेदारी है, आपने विभागीय पुस्तकालयों में 'यूथ को जोड़ो' अभियान चलाने की बात कही है, इसमें किस प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी?

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के तहत संचालित राज्य, मंडल और जिला स्तर पर संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में 'यूथ को जोड़ो' अभियान चलेगा। इसके लिए सभी पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा अपने पुस्तकालय की विशेषताओं और वहां उपलब्ध 'ज्ञान कोष' के बारे में 'ब्रोशर' तैयार किए जा रहे हैं। जुलाई-अगस्त माह में ये लाइब्रेरियन युवाओं को सार्वजनिक पुस्तकालयों से जोड़ने के लिए विशेष कैम्पेनिंग करेंगे। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सावित्री बाई फुले वाचनालय स्थापित करने, मंडल, जिला और पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत सभी पुस्तकालयों में पुस्तकों का सॉफ्टवेयर आधारित डेटा बैंक तैयार करने, स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए कंप्यूटर और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने और सीसीटीवी कैमरों से वंचित 'लाइब्रेरीज' में इन्हें शीघ्रता से इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बात पर पूरा फोकस है कि हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय इंफोर्मेशन हब बनें। सभी गवर्नमेंट लाइब्रेरी को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर प्रदेश में जिला एवं मंडल स्तर पर संचालित प्रमुख 47 पुस्तकालयों के लाइब्रेरियन का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इसके माध्यम से सभी गतिविधियों को रीडर्स फ्रेंडली बनाने के लिए सकारात्मक सुधार किये जा रहे हैं।

स्मार्ट हो रही राजस्थान के विद्यालयों की कक्षाएं

■ **डॉ. आशीष खण्डेलवाल**
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित कर रही है। लर्निंग आउटकम्स को पहले से बेहतर करने और डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आईसीटी योजना के तहत लगातार विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार करवा रही है। अब तक प्रदेश के आठ हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार करवाए जा चुके हैं।

इन्फोर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना के तहत आईसीटी कंप्यूटर लैब बनाई जा रही हैं। इसके तहत स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास रूम में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित जैसे विषयों की क्लासेज विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन और ई-कंटेंट के माध्यम से पढ़ा सकेंगे। स्मार्ट क्लास रूम में इंटरनेट सुविधा युक्त स्मार्ट टेलीविजन और हाईटेक प्रोजेक्टर भी लगाए जा रहे हैं।

सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग से विद्यालय स्तरीय निष्पादन क्षमता के संवर्धन तथा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुगम, सुरुचिपूर्ण और सर्व सुलभ बनाने के लिए आईसीटी/कल्प उपकरणों की व्यवस्था द्वारा वर्तमान

पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध कर विद्यार्थियों को डिजिटल विश्व से आत्मसात करवाने और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाने

हेतु राज्य के विद्यालयों में आई.सी.टी./कल्प (कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम) का उपयोग किया जा रहा है। विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का उपयोग दो दृष्टिकोणों से किया गया है, आईसीटी स्वयं एक विषय के रूप में तथा दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संवर्धन उपकरण के रूप में।

स्मार्ट क्लासरूम के उद्देश्य

- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीक के संवर्धन हेतु वातावरण निर्माण के माध्यम से गुणवत्ता प्रदान करना।
- आई.सी.टी./कल्प योजना द्वारा उपलब्ध सामग्री और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता करना।
- शिक्षण और अधिगम के लिए आई.सी.टी./कल्प उपकरणों की व्यवस्था से वर्तमान पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध करना।
- विद्यार्थियों को प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना।
- विद्यार्थियों को आई.सी.टी./कल्प योजना के उपकरणों के माध्यम से प्रभावी अधिगम वातावरण निर्माण कराना।
- विद्यालयों में स्वाध्याय की सहायता से समालोचना चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना। इससे कक्षा वातावरण शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होगा।
- कंप्यूटर शिक्षा द्वारा कक्षा का वातावरण शिक्षक केंद्रित न रहकर विद्यार्थी केंद्रित करने के प्रयास करना।

ई-ज्ञान पोर्टल

राज्य में सभी छात्र-छात्राओं हेतु ई-कंटेंट सर्वसुलभ करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ई-ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई। विद्यार्थी इस पोर्टल की मदद से अपना ज्ञान निरंतर अपग्रेड कर सकते हैं

स्मार्ट क्लास रूम योजना के तहत आईसीटी कंप्यूटर लैब बनाई जा रही हैं। इसके तहत स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास रूम में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित जैसे विषयों की क्लासेज विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन और ई-कंटेंट के माध्यम से पढ़ा सकेंगे। स्मार्ट क्लास रूम में इंटरनेट सुविधा युक्त स्मार्ट टेलीविजन और हाईटेक प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं।

दीक्षा राइज पोर्टल

राज्य में सभी छात्र-छात्राओं हेतु ई-कंटेंट सर्वसुलभ करवाने के लिए एमएचआरडी, नई दिल्ली एवं एससीईआरटी, उदयपुर के सहयोग से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु दीक्षा राइज पोर्टल की स्थापना एवं इसका विकास किया जा रहा है।

प्रदेश के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम

राज्य सरकार प्रदेश के मदरसों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इसके लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में 13.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रथम चरण में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है।

उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर लिखते

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

- **पवन शर्मा,** सहायक निदेशक, जनसंपर्क
- **मोहित जैन,** सहायक जनसंपर्क अधिकारी

निजी विद्यालयों में भारी फीस के बोझ को खत्म कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस योजना की शुरुआत जून, 2019 में की गई। कक्षा 1 से 12 तक संचालित ये विद्यालय शुरुआत में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू किए गए थे। इन विद्यालयों की अपार सफलता के बाद राज्य सरकार द्वारा 5 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों और गांवों में भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोलने का निर्णय किया गया।

अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन विद्यालयों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। इसी कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों के इतिहास में पहली बार बहुत ज्यादा आवेदन के कारण विद्यार्थियों को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश देना पड़ा। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक -एक हजार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) और खोलने की घोषणा की है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर बनाने और 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की भर्ती की जा रही है ताकि प्रदेशभर के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) का पूरा लाभ मिल सके।

नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन है- शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका संचालित की जा रही है। राजस्थान अंग्रेजी माध्यम में राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन करने वाला वर्तमान में देश का एकमात्र राज्य है। राज्य में शैक्षिक उन्नयन के सरकार के भगीरथी प्रयास निश्चय ही पूर्ण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के धरातल पर पूरी तरह खरे साबित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कमजोर तबके के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की पुनीत मंशा से आरंभ की गई महती योजना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) ने राजस्थान में शैक्षिक उन्नयन की तस्वीर और कमजोर तबके की तकदीर बदल कर रख दी है। कुछ ऐसा ही मंजर है अजमेर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकंडरी स्कूल वैशाली नगर का। इस विद्यालय में पूर्व में विद्यार्थी केवल हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे। आज अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनने के बाद यहां की छटा ही बदल गई है। यह स्कूल साधारण स्कूल से स्मार्ट स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया है और 539 विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे जब फर्राटे से अंग्रेजी में बात करते हैं तो लगता है कि किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से बात हो रही है।

स्कूल के नवीं कक्षा के छात्र आदित्य कुमार, छात्रा दिशा अलवानी व 11वीं की छात्रा वंशिका साहू जैसे कई बच्चे हैं जो साधारण परिवारों से हैं। इन्हें जब

गुणवत्ता के साथ-साथ कंप्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि वे अच्छी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल अब सहज ही हासिल कर पाएंगे।

चाय की दुकान चलाने वाले छात्रा दिशा के पिता पर पढ़ाई के लिए भारी खर्च उठाना बड़ी चुनौती थी। वे सरकार के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही शिक्षा को बच्ची के लिए सरकार की अनूठी सौगात मानते हैं।

आईएएस बनने का सपना लेकर पढ़ रही साधारण मैकेनिक की बेटी वंशिका से बात करने पर लगा कि यदि जीवन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल बड़ी नहीं हो सकती। फरटिदार अंग्रेजी में जवाब देते हुए वंशिका क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही स्कूल में बेहतर वातावरण के लिए खुशी जाहिर करते हुए कमजोर तबके को ऊंचा उठाने के लिये सरकार का आभार जताती है।

शाला की प्रधानाचार्य का कहना है कि 2019 से प्री-प्राइमरी से लेकर अब तक स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें अमीर-गरीब का भेद किये बगैर सभी बच्चों को आदर्श वातावरण प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लक्ष्य के साथ ही सभी शिक्षक एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ है। प्राइमरी लेवल पर तो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर गतिविधियों से आनंददायी शिक्षा का माहौल दिया जा रहा है। ड्रॉप आउट का तो सवाल ही नहीं है।

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित कला महोत्सव में भाग लेने गए विद्यालय के सभी बच्चों ने इंस्पायर अवॉर्ड जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। विद्यालय की कक्षा 6 के मयंक व सोनू और कक्षा सात की जया खान जहां इंग्लिश मीडियम के अनुभव से रोमांचित हैं वहीं ये बच्चे सरकार से फ्री यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री, मिड डे मील जैसी सुविधाओं से उन्हें व उनके साधारण परिवार को मिल रहे संबल के लिए बरबस ही सरकार के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते नजर आते हैं।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) रोलसाहबसर, सीकर की छात्रा आर्युषी भांभू के पिता दिव्यांग हैं और अपनी पत्नी के साथ खेती करते हैं। आर्युषी के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) को शुरू कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे उसके जैसे कम आर्थिक संसाधनों वाले परिवारों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उसने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न सहशैक्षणिक गतिविधियां जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि का आयोजन होता रहता है। इसके साथ ही विद्यालय में समय- समय पर खेलकूद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है जो उनके सर्वांगीण विकास में लाभदायक है। हाल में आर्युषी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा में बिना किसी कोचिंग के 96.83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय वह विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत, पढ़ाने की शैली व प्रेरणा को देती है। वर्तमान में वह भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान जैसे विषयों के साथ 11वीं कक्षा में है और भविष्य में डॉक्टर बनकर जन सामान्य की सेवा करना चाहती है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) पूरे देश भर में एक मॉडल स्कूल के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), विद्याधर नगर, जयपुर के प्रधानाध्यापक बच्चू सिंह धाकड़ बताते हैं कि इन विद्यालयों के माध्यम से राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी कारण नहीं छोड़ा है जिससे की कोई पढ़ाई से वंचित रहे। विद्यालय में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क यूनिफार्म, मिड-डे मील के तहत पोषाहार, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध, छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन, ट्रांसपोर्ट वाउचर आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ सहशैक्षणिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है।

प्रत्येक शनिवार 'नो बैग डे' के रूप में मनाया जाता है जिसमें खेलकूद, वाद-विवाद, पोस्टर निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रतिबद्ध है, इसलिए समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्पोकन इंग्लिश लर्निंग आदि का आयोजन होता है। विद्यालयों में दी जा रही इन बेहतरीन सुविधाओं का परिणाम यह है कि अब काफी विद्यार्थी निजी विद्यालयों को छोड़कर इन विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं। आज कई राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों के बच्चे इन राजकीय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) को राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना को प्रभावी बनाने हेतु दृष्टि पत्र (VISION- 2028) भी तैयार किया गया है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जारी श्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर जिले में अव्वल रहा है। इसमें सभी कक्षा कक्ष स्मार्ट कक्ष हैं। हर कक्ष में प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड हैं। विद्यालय में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे विद्यालय में होने वाली सभी गतिविधियां से प्रधानाचार्य की निगरानी में रहती हैं। यहां के दो विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता और 21 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय खेलों में हुआ है। विद्यालय में गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है जिसमें पौधों पर नाम के साथ क्यूआर कोड लगवाया गया है जिसे स्कैन करने पर पौधे की समस्त जानकारी प्राप्त होती है।

नौनिहालों को मिल रहा पोषण

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में युवा शक्ति की अहम भूमिका होती है। जिस देश की युवा शक्ति मजबूत होती है वह देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। युवा शिक्षित स्वस्थ और काबिल हों, इसके लिए जरूरी है कि बचपन में ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022- 23 के राज्य बजट में सरकारी स्कूलों, मदरसों तथा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को मिड-डे मील योजना के अंतर्गत दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की। घोषणा की पालना में 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई। राज्य द्वारा वित्त पोषित इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें पाउडर मिल्क की विद्यालयों में आपूर्ति राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) के द्वारा की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 मिलीलीटर दूध तैयार कर बांटा जा रहा है जबकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क दूध से 200 मिलीलीटर दूध तैयार करने के पश्चात दिया जाता है। दूध को स्वादिष्ट और मीठा बनाने के लिए सरकार द्वारा चीनी भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं को प्रार्थना सभा के तुरंत पश्चात दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति के पास है।

■ **सुधाकर सोनी**
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

दूध की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर ही यह विद्यार्थियों को वितरित किया जाता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए दूध वितरण का रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से राज्य के लगभग 69 लाख 22 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

योजना की सफलता को देखते हुए तथा बच्चों को और अधिक पोषण दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य बजट 2023- 24 में विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। नवीन सत्र 1 जुलाई, 2023 से विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं एवं पाउडर मिल्क के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सरकार की इस अनूठी पहल से विद्यालयों मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों और किशोर- किशोरियों को अच्छा पोषण तो मिलेगा ही, विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी। इससे आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी। साथ ही नामांकन में वृद्धि होगी तथा ड्रॉपआउट की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी। समाज के गरीब तबके के लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

नई गणवेश में मिल रही खुशी और समानता की अनुभूति

■ डॉ. राजेश कुमार कुमावत
सहायक निदेशक, स्कूल शिक्षा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2021-22 के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के दो सेट दिए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ 29 नवंबर, 2022 को किया गया। यह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है।

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों के लिए यूनिफॉर्म हल्के नीले रंग की कमीज तथा गहरे भूरे/धूसर रंग की नेकर/ पेंट तथा छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता/शर्ट तथा गहरे भूरे रंग की सलवार/स्कर्ट एवं गहरे भूरे/धूसर रंग का दुपट्टा (चुन्नी) निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2022-23 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के 66,46,163 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के दो सेट वितरित एवं यूनिफॉर्म सिलाई हेतु 200 रुपये की राशि विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। अब तक 49,34,609 विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति विद्यार्थी डी.बी.टी. की जा चुकी हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के नामांकित 27,881 विद्यार्थियों को उनकी यूनिफॉर्म का रंग डिजाइन अन्य राजकीय विद्यालयों से अलग होने के कारण यूनिफॉर्म के स्थान पर इन्हें यूनिफॉर्म फैब्रिक एवं सिलाई

कक्षा 1 से 5 तक	कक्षा 6 से 8 तक
छात्रों के लिए शर्ट एवं पेंट/नेकर	छात्रों के लिए शर्ट एवं पेंट
छात्राओं के लिए शर्ट एवं स्कर्ट	छात्राओं के लिए कुर्ता, सलवार एवं दुपट्टा

की राशि 740 रुपये प्रति विद्यार्थी डी.बी.टी. के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राज्य सरकार ने 94.61 करोड़ रुपये की राशि राज्य मद से उपलब्ध करवाई है।

इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के निःशुल्क यूनिफॉर्म के दो सेट वितरण हेतु कुल राशि 500.10 करोड़ रुपये में से 325.87 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 12 फरवरी 2023 को की गई बजट घोषणा 2023-24 के मुताबिक आगामी वर्ष में भी इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की जाएंगी। सत्र 2023-24 में 69,57,657 विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएंगी एवं इस सत्र में 69,57,657 विद्यार्थियों में से 51,85,325 विद्यार्थी (सभी छात्राएं, एससी, एसटी और बीपीएल छात्र) की केंद्र एवं राज्य मद से 311.11 करोड़ की राशि वहन की जाएगी। इसके अलावा 17,72,332 (सामान्य, ओबीसी, एसबीसी छात्र) की यूनिफॉर्म की 106.33 करोड़ की राशि को राज्य मद से वहन किया जाएगा।

यूनिफॉर्म वितरण के कारण अभिभावकों को आर्थिक राहत तो प्राप्त हुई है, साथ ही विद्यार्थियों को विद्यालयों में निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा भी मिली है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी मुख्यधारा से जुड़े हैं। सभी छात्रों को समान गणवेश में होने से सामाजिक समरूपता एवं एकता की भावना विकसित हो रही है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक-बालिकाओं को नवीन गणवेश में खुशी व समानता की अनुभूति होती है।

राजस्थान के पुरातन कला संस्थान

■ डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली राजस्थान की सबसे पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना जयपुर की तत्कालीन रियासत के शासक कला प्रेमी और विरासत के संरक्षक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की। स्कूल 1857 ईस्वी में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसे मदरसा-ए-हुनरी यानी कला संस्थान के नाम से जाना जाता था। समय के साथ, संस्थान अपने पाठ्यक्रम में कला और शिल्प के चालीस विभिन्न विषयों के साथ कला के क्षेत्र में अग्रणी बन गया। इसे 1886 ई. में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान संस्थान राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट उपर्युक्त संस्थान का उत्तराधिकारी है, जिसने अब विजुअल शिक्षण और हुनर में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है।

संस्थान का एक गौरवशाली अतीत रहा है। इस कॉलेज के स्नातक समकालीन कला के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उनमें से अधिकांश ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कला के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। इस कॉलेज के संकाय सदस्य विभिन्न कला विषयों से स्वयं प्रतिष्ठित कलाकार हैं। उनके कार्यों को देश भर में, यहां तक कि विदेशों में भी मान्यता मिली है। संस्था के पास विभिन्न कला विषयों के लिए अच्छी तरह से स्थापित स्टूडियो हैं, जो अधिकांश आधुनिक उपकरणों और कच्चे माल की एक अद्भुत श्रृंखला से सुसज्जित हैं। कला के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक भी सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं और उन्हें सीखने और प्रगति करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। कॉलेज ललित कला विषयों पर लगभग 6,000 पुस्तकों के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय का भी दावा करता है, जिनमें से कुछ सबसे दुर्लभ हैं।

संस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है। कुछ साल पहले तक मीनाकारी के गहने तैयार करने के लिए भट्टी में पकाते थे, लेकिन अब भट्टी में पकाकर गहने तैयार करने वाले कारीगर नहीं रहे। इलेक्ट्रिक फर्न में पकाने की वजह से खास चटक लाल, सफेद चलमा, फाकताई (जिसे कबूतरी रंग भी कहते हैं) रंग गहनों में नहीं दिखते। यही वजह है कि मीनाकारी के काम में फर्क भी आ गया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नवाचारों को लेकर किशनपोल बाजार स्थित म्यूजियम ऑफ लेगसीज में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यहां राजस्थानी टेक्सटाइल, ज्वेलरी, स्टोन वेयर, इन-ले-वर्क, पेंटिंग व पॉटरी को प्रदर्शित किया जाता है।

म्यूजियम ऑफ लेगसीज

गौरतलब है कि म्यूजियम ऑफ लेगसीज का भवन पंडित शिवदीन का निवास स्थान था। वे सवाई राजा राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल (1825-1830) के दौरान उनके मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में 1857 में मदरसा-ए-हुनरी यानी कला प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान शुरू किया गया।

14 कैरेट गोल्ड से लिखी आयतें

आर्टिस्ट मिच के स्टूडियो में सफेद मार्बल पर कुरान की आयतें लिखी हैं। अक्षरों के ऊपर 14 कैरट गोल्ड का इस्तेमाल किया है।

12 फीट से लंबी कठपुतली

ऊपर की गैलरी में 12 फीट से बड़े आकार की कठपुतली लगाई है। कठपुतली कलाकार विकी भट्ट ने बनाई है। इसके जरिए राजस्थान की लोकप्रिय कठपुतली कला को दिखाया गया है।

400 किलो का फाउंटेन

शाहजहानी डिजाइन में ब्लैक मार्बल का फ्लोर फाउंटेन बनाया है जिसे मकराना माइंस मार्बल से लाया गया है। यह 400 किलो का फाउंटेन है।

तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री अशोक गहलोत 24 फरवरी, 1983 को रवींद्र मंच आर्ट गैलरी का अवलोकन करते हुए

फाकताई रंग के भट्टी में पकाए गए गहने

जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तब एमरल्ड व्हील की मदद से काटे जाते थे, जिसमें एक सिरे पर छोटा व्हील व दूसरे सिरे पर बड़ा व्हील रखते थे। एक उसे चलाता था दूसरा शख्स उसे काटता था। वहीं कुंदन मीनाकारी के गहने पहले भट्टी में पकाए जाते थे। भट्टी से निखर कर आने वाला रंग अब मीनाकारी में नहीं दिखता। भट्टी में पता चलता था कितने ताप पर कौन सा रंग आता था। इलेक्ट्रिक फर्न में पकाने की वजह से चटक लाल, सफेद चलमा, फाकताई रंग गहनों में नहीं दिखते।

महाराजा स्कूल - उत्तर भारत का पुरातन महाविद्यालय

उत्तर भारत के इस सबसे पुरातन महाविद्यालय की स्थापना सन् 1844 में सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। उस समय इसका नाम महाराजा स्कूल था जो हवामहल के पास माणक चौक में स्थित था। इसकी इमारत की अभिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकारों ने की थी। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन 6 महाविद्यालयों में से एक है। इसमें सर्वप्रथम 40 विद्यार्थियों को हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। पंडित शिवदीन स्कूल के पहले प्रिंसिपल बने एवं सन् 1885 तक रहे।

कालांतर में इस महाविद्यालय में तेजी से वृद्धि हुई और सन् 1852 में इसे श्री हरिदास शास्त्री के समय संस्कृत कॉलेज बनाने के लिए विभाजित किया गया। पंडित शिवदीन के बाद, मुंशी किशन स्वरूप मुखर्जी 1865 में हेडमास्टर के रूप में इस स्कूल में शामिल हुए। जनाब मीर मुराद अली फारसी के शिक्षक थे, श्री बालमुकुंद शास्त्री और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री संस्कृत के शिक्षक थे। इस दौरान श्री माखनलाल हिंदी शिक्षक थे।

वर्ष 1873 में मास्टर कांतिचंद्र मुखर्जी के हेडमास्टर बनने के बाद, इस कॉलेज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। सन् 1875 तक छात्रों की संख्या 800 तक पहुंच गई और यह क्रम जारी रहा। बाद में इसे 1890 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री के लिए संबद्ध किया गया और 1896 में स्नातकोत्तर के लिए अपग्रेड किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पुरस्कार की स्थापना लॉर्ड नॉर्थब्रुक के स्कूल जाने के बाद की गई थी, जबकि मेवाड़ गोल्ड मेडल महाराणा फतह सिंह की यात्रा से शुरू किया गया था।

महाराजा माधोसिंह (द्वितीय) को सम्मानित करने के लिए 10 अप्रैल, 1908 को इस कॉलेज के पुराने भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में ए.जी.जी. काल्विन ने महाराजा को एलएलडी डिग्री एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया। इतिहास, दर्शन और गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 1927 में शुरू किया गया। कॉलेज को 1933 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका निर्माण उस समय 8.5 लाख रुपये की लागत से किया गया था।

इस कॉलेज के परिसर में अभी भी नींव का पत्थर देखा जा सकता है। वाणिज्य को 1940 में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था और 1947 में फैकल्टी ऑफ लॉ की स्थापना की गई थी। यह कॉलेज लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षा प्रदान करता रहा था, लेकिन जब 1944 में लड़कियों के लिए महारानी कॉलेज की स्थापना हुई, इसके बाद इस कॉलेज में केवल लड़कों को शिक्षा मिल रही है। यह कॉलेज 1962 में राजस्थान विश्वविद्यालय का एक संघटक महाविद्यालय बन गया।

प्रख्यात संस्कृत विद्वान, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने अपने ग्रंथ जयपुर वैभवम में इन शब्दों में इस कॉलेज की सराहना की थी, "उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षक इस स्वच्छ और सुंदर इमारत में पढ़ाते हैं। इस कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।" सवाई मानसिंह स्टेडियम की स्थापना से पूर्व तक, इस कॉलेज के खेल मैदानों में 1961 में एमसीसी द्वारा खेले गए क्रिकेट मैच सहित कई अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम देखे गए जहां श्री सलीम दुर्रानी मुख्य आकर्षण थे।

कॉलेज के पास आज भी एक ऐतिहासिक आगंतुक पुस्तक (Visitor's Book) है, जिसमें 1870 और 1929 के बीच डॉ. डब्ल्यू लांडऊ (1880), ई वेदेनबर्ग, क्यूरेटर जीएसआई (1903), अल्बर्ट अल्फारवेल (1905), बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह (1915) और प्रोफेसर मेघनाथ साहा (1926) सहित इस महाविद्यालय का दौरा करने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों का विवरण और टिप्पणियां अंकित हैं।

इस कॉलेज के कुछ प्रमुख पूर्व छात्रों में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा की पत्नी श्रीमती विमला शर्मा, यूके में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री एल.एम. सिंघवी, गुजरात के पूर्व राज्यपाल पं नवल किशोर शर्मा, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री एन.एल. टिबरेवाल और कई अन्य विख्यात हस्तियां शामिल रही हैं। •

चिकित्सा सुविधाओं के साथ

चिकित्सा शिक्षा में भी अग्रणी है राजस्थान

■ राम सिंह
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

राजस्थान में प्रति 50 लाख की जनसंख्या पर 1.99 यानी तकरीबन दो राजकीय मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों को शामिल करते हुए यह संख्या लगभग 2.5 है जो देश के कई राज्यों से बेहतर है।

राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 25 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रदेशवासियों के लिए सभी प्रकार की आईपीडी एवं ओपीडी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

आमजन को इन लोककल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने आधारभूत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर की चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ टर्सरी स्तर की चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के मामले में देश में एक मिसाल कायम की है। राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां प्रत्येक जिले में एक मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाकर कॉलेज खोले गए हैं। अब राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ राजकीय नर्सिंग कॉलेज की सुविधा भी राज्य के निवासियों को उपलब्ध हो रही है।

राज्य में वर्तमान में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसके अलावा एम्स जोधपुर और ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर भारत सरकार के अधीन हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़, सिरोही और धौलपुर 100-100 सीटों के साथ प्रारंभ कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अलवर, बूंदी, करौली, हनुमानगढ़ और दौसा के लिए एलओआई प्राप्त हो गई है और इस वर्ष ये 5 मेडिकल कॉलेज और प्रारंभ हो जाएंगे। इनके अलावा वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में घोषित प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर सहित 10 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोतों राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर में जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। राजस्थान में निजी क्षेत्र के 9 मेडिकल कॉलेज हैं और राज्य सरकार निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति लाने पर भी काम कर रही है।

चिकित्सकों की उपलब्धता पर विशेष फोकस

सरकार ने चिकित्सा संस्थानों के सफल संचालन के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया है। राजकीय क्षेत्र में वर्ष 2018 में जहां 1 हजार 850 एमबीबीएस सीटें थीं जो वर्ष 2022 में बढ़कर 3 हजार 330 हो गई हैं। गत चार वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में लगभग 80 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। आगामी वर्ष तक यह संख्या बढ़कर 3 हजार 830 हो जाएगी।

राज्य में पीजी की सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है।

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2018 में 960 पीजी सीटें थी जो बढ़कर 1690 हो गई हैं।

संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज

राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। जयपुर में सत्र 2021-22 में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कोर्स आरयूएचएस में संचालित कॉलेज में 25 सीटों के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। जोधपुर एवं उदयपुर में सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है तथा शेष चार संभागों में अगले सत्र में कोर्स प्रारंभ हो जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 175 छात्र लाभान्वित होंगे।

मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण

हर जिले में नर्सिंग कॉलेज

राज्य के सभी जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 तक प्रदेश में राजकीय क्षेत्र के मात्र 10 नर्सिंग कॉलेज संचालित थे। गत चार वर्षों में कुल 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए जिससे 1,560 नर्सिंग सीटों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बजट घोषणा 2023-24 में चार अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में राजकीय क्षेत्र में कुल नर्सिंग सीटों की संख्या बढ़कर 2,630 हो जाएगी।

प्रदेशभर में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार

राज्य में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागीय मेडिकल कॉलेजों में एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो-सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ओंको-सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की गई है। साथ ही राजमेस द्वारा संचालित 7 मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी की सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य में चार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में प्रारंभ किए गए हैं। इसके अलावा राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर में प्रारंभ किया गया है।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में 588 करोड़ रुपये की लागत से 1,200 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में आईपीडी टॉवर के लिए उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपये तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2023-24 के बजट में एसएमएस, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ हार्मोन एंड मेटाबोलिक डिसऑर्डर, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तथा आरयूएचएस के अंतर्गत सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबीलिटेशन के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पाइरेटरी डिजीजेज स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिन पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में कैंसर के इलाज के लिए उच्चस्तरीय तकनीक की लीनियर एक्सीलेटर मशीनें स्थापित की जा रही हैं। जयपुर और जोधपुर में डीएसए मशीन मस्तिष्क रोगों के निदान के लिए स्थापित की गई हैं।

एसएमएस, जयपुर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है तथा जोधपुर में इस वर्ष प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना तथा उच्चस्तरीय मशीनों के उपयोग से कई दुर्लभ एवं असाध्य रोगों का इलाज कर मरीजों का जीवन सुगम किया गया है। इसके अंतर्गत जयपुर में मेडिसिन विभाग में बोनमेरो ट्रांसप्लान्ट तथा स्टेट कैंसर इस्टीट्यूट में ओपीडी में बोनमेरो ट्रांसप्लान्ट संपन्न किया गया।

राज्य के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू बेड्स की संख्या 600 से बढ़ा कर 2,600 की गई है, जिसके परिणामस्वरूप शिशु मृत्युदर के अंकों में बेहतरीन सुधार हुआ है।

अन्य सेवाओं में भी विस्तार

राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दैनिक क्षमता 16,037 सिलेंडर के कुल 121 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 18 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं जिनकी दैनिक क्षमता 38,500 सिलेंडर है।

एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में जीनोम सिक्वेंसिंग लेबोरेटरीज स्थापित की गई हैं।

ज्ञान संकल्प पोर्टल

भामाशाहों को एक साथ लाने के लिए शिक्षा विभाग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

■ डॉ. नीरू पोटलिया
सहायक निदेशक, स्कूल शिक्षा

शिक्षा जीवन की वह पूंजी है जिसे ग्रहण करके व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। आगे निकलने की दौड़ में आज शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। प्रदेश के सभी बच्चों को शिक्षा मिले इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में राजकीय स्कूलों की व्यवस्था की गई। इन राजकीय विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से युक्त कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के साथ-साथ कई भामाशाह, दानदाता आगे आकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के विद्यालयों को दिन-प्रतिदिन मिल रहा संबल इस बात का प्रमाण है कि वीरों की भूमि राजस्थान अब दानवीरों की भूमि के नाम से भी जानी जा रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु भामाशाहों ने सराहनीय संबल प्रदान किया है। भामाशाहों को प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो इस श्रेणी को विशेष बनाता है। स्कूल शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों को तथा संभावित दानदाताओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से कंपनियों, ट्रस्टों और व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का संचालन कर रहा है।

ज्ञान संकल्प पोर्टल ने राजस्थान की शिक्षा को न सिर्फ एक नया आयाम दिया बल्कि उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से आमजन शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देकर राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को संसाधनों से युक्त कर पुनीत कार्य कर रहा है।

इसकी बानगी कालूराम कानाराम विश्नोई संस्थान के द्वारा लगभग 2 करोड़ 28 लाख की लागत से जालोर जिले के हरियाली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन, जंवारी लाल चैनरूप बैथ चैरिटेबल संस्थान के द्वारा लगभग 94 लाख की लागत से चूरू जिले के परिहारा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन, जीडीए फाउंडेशन संस्थान के द्वारा लगभग 3 करोड़ 50 लाख की लागत से पाली जिले के बालराई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीनतम व आधुनिक अवसंरचना से बने भवन हैं। पर्याप्त कक्षा-कक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय भवन, मिड-डे मिल कक्ष, शौचालय, रनिंग वाटर सुविधा, फर्नीचर, सूचना प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा डिजिटल लैब से युक्त ये विद्यालय छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण जरिया बन रहे हैं।

राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, कॉरपोरेट, गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित व्यक्तिगत दानदाता व भामाशाहों को सहायता प्रदान करने में भूगोल व दूरी की कठिनाइयां को दूर करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत 5 अगस्त, 2017 को की गई। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भामाशाह और औद्योगिक घराने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत जुड़कर सीधे राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में किए जा रहे नवाचार एवं आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

ज्ञान संकल्प पोर्टल एक ऐसा सशक्त ऑनलाइन माध्यम है, जो राजकीय विद्यालयों को आधारभूत संरचना व वित्तीय संबल प्रदान कर रहा है और इसके साथ सीएसआर के तहत कार्य करवाने हेतु कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भामाशाहों, दानदाताओं, औद्योगिक संस्थानों को कार्यक्षेत्र देने के साथ ही क्राउडफंडिंग के माध्यम से आवश्यक धन राशि का संग्रहण व प्रबंधन कर रहा है।

ज्ञान संकल्प पोर्टल पर सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय सहयोग हेतु उपलब्ध हैं। यही नहीं, भामाशाहों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पोर्टल के माध्यम से दी गई सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत छूट का प्रावधान भी है।

पोर्टल के माध्यम से शिक्षा निधि में सहायता देने हेतु भामाशाह, दानदाता एवं कंपनियों के लिए विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं। इंडिविजुअल डोनर व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही नई पहल में अपना योगदान देकर प्रदेश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। कॉरपोरेट डोनर के माध्यम से एक कंपनी द्वारा एक विद्यालय को गोद लेकर ब्लॉक स्तर पर सुधार कार्य या जिला स्तर पर उच्च गुणवत्ता की बुनियादी ढांचे की आपूर्ति उपलब्ध कराकर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों के लिए विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न श्रेणियां उपलब्ध हैं, जैसे — विद्यालय गोद लेना, कंपनी, भामाशाह द्वारा प्रोजेक्ट बनाकर (क्रिएट योर ऑन प्रोजेक्ट), विभाग द्वारा प्रदर्शित प्रोजेक्ट में योगदान देकर (सपोर्ट ए प्रोजेक्ट), मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग देकर विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को दान देकर (डोनेट टू ए स्कूल) आदि।

भामाशाह, दानदाता औद्योगिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन उनके स्वयं के द्वारा या स्वयं द्वारा चिह्नित सेवा प्रदाता के माध्यम से अथवा परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर सरकार के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 22.42 करोड़ रुपये की राशि ब्याज सहित प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि में से प्रत्येक जिले के एक आदर्श योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के क्रम में 33 जिलों के 33 आदर्श योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों हेतु प्रत्येक विद्यालय को अधिकतम 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 97 विद्यालयों में आवश्यकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राशि से अब तक 33 जिलों में 130 विद्यालयों में 21.96 करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

डोनेट टू ए स्कूल श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त राशि को सभी विद्यालय जिन्होंने शाला दर्पण पर एसडीएमसी व एसएमसी के खातों का सत्यापन कर दिया है, इस श्रेणी के अंतर्गत प्रदेश के करीब 58,000 विद्यालय लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, डोनेट टू ए स्कूल तथा सपोर्ट ए प्रोजेक्ट श्रेणियों के अंतर्गत सत्र 2022-23 तक लगभग 62 करोड़ की नकद राशि विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त हुई है।

राजकीय विद्यालयों हेतु विभिन्न दानदाताओं, भामाशाहों, सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाने हेतु अनुमोदन भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ क्रिएट योअर ऑन प्रोजेक्ट के तहत 411 प्रोजेक्ट के तहत अब तक कुल 249.26 करोड़ रुपये के कार्यों का अनुमोदन हुआ है। 27 विद्यालयों को गोद लेकर विकास करने हेतु लगभग 8 करोड़ की राशि के कार्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ज्ञान संकल्प पोर्टल पर 2.33 लाख से अधिक भारतीय व्यक्तिगत दानदाता, 97 अनिवासी भारतीय सहित 875 से अधिक कंपनी व गैर सरकारी संस्थाएं जुड़ी हैं।

राजस्थान में नौनिहालों की शिक्षा की दिशा में भामाशाहों के द्वारा दिया गया, योगदान उनके बेहतर भविष्य की नींव रख रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग के अद्वितीय प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से प्रदेशभर के विद्यालयों को आधारभूत आधुनिक व नवीनतम तकनीक युक्त भवन तथा भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाहों के जागरूक प्रयास सराहनीय हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालराई

उच्च शिक्षा के अभिनव आयाम

■ डॉ. सुधीर सोनी
शिक्षाविद

उच्च शिक्षा में देश में राजस्थान की एक विशेष भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मौजूदा सरकार की शुरुआती बजट घोषणाओं में ही उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इसके बाद निरंतर उच्च शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। खासतौर पर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी जो संसाधनों के अभाव में किसी बड़े शहर में नहीं जा पाते थे और बालिकाएं जो अपनी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थिति के चलते उच्च शिक्षा से नहीं जुड़ पाती थी, के साथ उपेक्षित एवं वंचित तबके के लिए राजस्थान की उच्च शिक्षा में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 30 हजार बच्चों को अनुप्रति योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयार करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों की विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की छात्रा/ महिला के प्रवेश के समय लिये जाने वाली राजकीय निधि कोष की राशि माफ की गई है। निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं/प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी राजकीय महाविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को क्रमशः 5 व 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व स्नातक पार्ट प्रथम में सभी संकायों (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ायी गईं। समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 से प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को उस माह में पढ़ाये गए पाठ्यक्रम में से कक्षा टेस्ट लिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है। समस्त राजकीय महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय के समस्त सेक्शनों को पांच हाउसेस (पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि) में बांटा गया है ताकि महाविद्यालय में होने वाली समस्त सहशैक्षणिक गतिविधियां अंतर हाउस के माध्यम से सम्पन्न की जा सकें।

दूरदराज के क्षेत्रों और कस्बों में खुले महाविद्यालय

शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। उच्च शिक्षा अपने वास्तविक परिदृश्य को प्राप्त हो उसके लिए सतत प्रयास किये जा रहे है। यही वजह है कि बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों, छोटे कस्बों

में भी उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए महाविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। 500 बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन पर कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। इस तरह दूरस्थ क्षेत्रों में भी सह शिक्षा और खासतौर पर केंद्रीय बालिका शिक्षा के महाविद्यालय खोले गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े और वे अपनी पारिवारिक परिस्थिति के अनुरूप अपने निकटतम महाविद्यालय में शिक्षित हो सकें।

विश्वविद्यालयों की परिधि का विकास

समय की मांग के अनुरूप शोध एवं रचनात्मकता को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महाविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालयों की परिधि का भी निरंतर विकास किया है। राजस्थान में राजकीय स्तर पर 28 विश्वविद्यालय संचालित हैं जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, कृषि, खेल, संस्कृति शिक्षा, तकनीक आदि संकायों को सम्मिलित करते हुए समय की एक बड़ी मांग को पूरा करते हैं। विशेष रूप से राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में हाल में खोले गए विश्वविद्यालय जैसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बृज विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय, शेखावटी विश्वविद्यालय आदि ने अपनी शैक्षिक गुणवत्ता और सरोकारों को निरंतर कायम रखा है। प्रदेश में संचालित प्रमुख विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं:

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
5. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
6. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
7. जगदगुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
8. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
9. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
11. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
12. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
13. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
14. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
15. सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
16. गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
17. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
18. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
19. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
20. राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं
21. श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
22. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
23. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
24. राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
25. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
26. हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
27. डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
28. एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर

शिक्षकों के सरोकारों की पूर्ति

आज के समय की सबसे बड़ी मांग शिक्षा है। राज्य सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण इकाई तभी हो सकते हैं जब उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसलिए नीति आयोग के प्रारूप के अनुरूप सभी संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए अभिनव प्रयास किए गए हैं। उच्च शिक्षा में अध्यापन के लिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है कि वहां के अध्यापक न केवल रचनात्मक सरोकारों से जुड़े रहें बल्कि शोध की दिशा में उनको अभिनव अवसर प्राप्त होते रहें। वे निरंतर शोध पत्र लेखन, पुस्तक लेखन, नवाचार, नवीनतम अध्यापन प्रविधियों से जुड़े रहें। साथ ही देश - विदेश के विविध शिक्षा - सरोकारों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, समारोह आदि के माध्यम से भी अपने अभिनव विचारों और शोध पत्रों को आकार देते रहें। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग निरंतर कार्य करता है और देश-विदेश में आयोजित होने वाले विविध आयोजनों में गुणवत्तापूर्ण तरीके से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को जोड़ता है। इसके अलावा समय-समय पर देश-विदेश में आयोजित होने वाले शैक्षिक सम्मेलनों में भी शिक्षकों की उपस्थिति से रचनात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह राज्य सरकार की अभिनव सोच का ही परिणाम है कि आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के अनुरूप सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य पदनाम दिया गया है। विशेष रूप से राजकीय महाविद्यालयों में हाल में आचार्य पदनाम दिया जाना और उससे जुड़े शैक्षिक सरोकारों की पूर्ति कर राज्य सरकार ने एक अभिनव आयाम स्थापित किया है। इससे न केवल राज्य में शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा बल्कि विद्यार्थियों में

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अध्यापन का भी अभिनव प्रसार हो सकेगा।

विद्या संबल जैसी योजना के माध्यम से भी नए खुले महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यार्थी को आगामी भविष्य की मांग के अनुरूप आधार दिया जा सके तो वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इसी चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विविध विषयों के अध्यापन की व्यवस्था की है। ज्ञानगंगा प्रोग्राम के तहत शिक्षकों में क्षमता विकास, शिक्षण कौशल एव शोध प्रोत्साहन के लिए विभाग स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सार्थक शिक्षा के सभी पक्षों का समावेश

विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के सामने कई चुनौतियां हैं। जब तक आज का विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से उचित आजीविका के अवसर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उच्च शिक्षा अपने एक पायदान से पीछे रहेगी। लेकिन जब शिक्षा विद्यार्थी को योग्य बनाने में समर्थ हैं, इससे एक विद्यार्थी अपने कदमों पर खड़ा होकर अच्छी नौकरी पा सके, आजीविका के उपाय भी कर सके तो माना जाता है कि दी जा रही शिक्षा सार्थक है। एक विद्यार्थी जब स्वयं अपना विकास करेगा, साथ ही अपने परिवार और समाज का विकास भी करेगा, तभी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। वह अपने कदमों पर खड़ा होकर अपने देश और समाज का नाम रोशन करे ऐसे पक्षों को शिक्षा में समावेश करने का प्रयास किया गया है। पूरे राजस्थान में फैले राजकीय महाविद्यालय इसी चुनौती को एक सकारात्मक परिधि के रूप में सामने लाते हैं। विशेष रूप से कला संकाय इन सभी महाविद्यालयों में खोला गया है। साथ ही क्षेत्र विशेष की मांग के अनुरूप गारमेंट प्रोडक्शन, जियोलॉजी, उर्दू, फारसी, विजुअल आर्ट्स जैसे नवीनतम विषय भी रखे गए हैं। जिन क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्यापन की मांग है वहां स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। विशेष रूप से विज्ञान संकाय के महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की चुनौती को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय लैब का निर्माण किया गया है और उनमें गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के साथ केमिकल आदि मुहैया कराए गए हैं ताकि विद्यार्थी विज्ञान संकाय की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अंग्रेजी में निपुणता के लिए लैंग्वेज लैब

उच्च शिक्षा में भाषा का विशेष महत्व है। इसके अलावा विद्यार्थी समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी निपुण हो सकें इसके लिए महाविद्यालयों में विविध स्तरों पर लैंग्वेज लैब बनाई गई हैं। विद्यार्थी आधुनिक कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी की उच्चारण शुद्धता के साथ न्यूज रीडिंग जैसे पहलुओं को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से सीख सकते हैं।

महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण खेल संसाधनों का विकास

खेल वर्तमान समय की मांग हैं। खेल विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों से सामना करने की प्रेरणा भी देते हैं, इसीलिए सभी महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण खेल संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। बड़े खेल के मैदानों के साथ-

साथ वहां स्थानीय खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, जूडो आदि को सम्मिलित करते हुए खेलों के लिए एक रचनात्मक वातावरण का निर्माण किया गया है।

विद्यार्थियों में लीडरशिप का विकास

विद्यार्थियों में लोकतंत्र की भावना के अनुरूप लीडरशिप जैसे गुणों का विकास भी हो सके, इसके लिए छात्र संघ चुनावों को भी उच्च शिक्षा में फिर से शुरू किया गया है। लोकतंत्र की परंपरा के अनुरूप वे न केवल आगे आ सकें बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों की मांग के साथ-साथ विद्यार्थियों के मध्य उभर रही चुनौतियों का सामना करने के अपने सकारात्मक प्रयासों को भी एक अभिनव आयाम दे सकें। छात्रसंघ चुनावों के माध्यम से विद्यार्थियों को लीडरशिप का एक अभिनव मौका भी मिलता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री

किसी भी राज्य की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि वहां के शिक्षक विद्यार्थियों के लिए निरंतर आधारभूत शिक्षण पुस्तकों का निर्माण करते रहें। साथ ही राज्य के ज्यादातर विद्यार्थियों के माध्यम के मुताबिक हिंदी में आम विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री मिलती है, इससे रचनात्मक सरोकारों को नये आयाम मिलते हैं। यह राज्य सरकार का ही अभिनव प्रयत्न है कि उच्च शिक्षा में हिंदी की पुस्तकों के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी निरंतर कार्य कर रही है और विशेष रूप से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में विविध विषयों के लिए गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का निर्माण किया गया है। इससे एक ओर विद्यार्थियों को ज्ञान के संसाधन मिलते हैं वहीं वह अपने रचनात्मक विचारों को शिक्षकों के साथ पूरा कर सकते हैं। ज्ञानसुधा कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी क्षमता के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन के रूप में नि:शुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पर पंजीकृत लाखों विद्यार्थियों के लिए लाइव सेशन भी आयोजित करवाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों की वजह से राजस्थान की उच्च शिक्षा न केवल एक प्रतिमान बन रही है, बल्कि युवाओं को रचनात्मक और समाजोपयोगी सरोकारों से भी जोड़ रही है। •

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

पल्लवित हो रही बेटियों की प्रतिभा

■ दिनेश कुमार शर्मा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

कहते हैं कि जब एक बेटा शिक्षित होता है तो वह एक परिवार को रोशन करता है, लेकिन जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों को रोशन करती है। इसके बावजूद बेटियों की शिक्षा को एक लंबे अरसे तक संकीर्ण नजरिये से देखा गया और दोयम दर्जे पर रखा गया। लेकिन राजस्थान में हालात अब बदल रहे हैं। यहां बेटियों की शिक्षा को सरकार का भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से तालीम हासिल करने के बालिकाओं के अरमानों को पंख लग रहे हैं और समाज की सोच में भी आमूलचूल बदलाव आ रहा है।

राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा की अहमियत समझते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, शिक्षा सेतु योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आदि इस दिशा में उठाए गए राज्य सरकार के उल्लेखनीय प्रयास हैं। इसी क्रम में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने एवं आगामी कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रियदर्शिनी नाम दिया गया, के नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है।

बचपन से ही पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने की शौकीन रहीं प्रियदर्शिनी (इंदिरा गांधी) की सामान्य ज्ञान की जानकारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्हें देश-दुनिया का भी काफी ज्ञान था, जिसके कारण वे अभिव्यक्ति की कला में भी निपुण थीं। वे आत्मविश्वास से भरपूर थीं और अडिग निर्णयों के लिए जानी जाती थीं। कुछ इसी प्रकार का व्यक्तित्व प्रदेश की बालिकाओं का गढ़ने की मंशा से प्रतिवर्ष स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

मार्च, 2019 से इस योजना को लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं कक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अलग-अलग) की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत

शिक्षा की कक्षा-8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 संवर्गों की छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। जिन 8 संवर्गों की छात्राओं को यह पुरस्कार देय है उनमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल एवं निशक्त वर्ग शामिल हैं। वर्ष 2021-22 से व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में उक्त श्रेणियों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की 8-8 बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की 9 सीजीपीए या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली उपरोक्त श्रेणियों की राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी वर्ष 2021-22 से यह पुरस्कार देय है।

योजना के अंतर्गत आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्राओं को 40 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, जबकि दसवीं कक्षा एवं प्रवेशिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 75 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। वहीं, बारहवीं कक्षा एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक लाख रुपये की राशि एवं स्कूटी पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छात्रा द्वारा परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही, छात्रा का अगली कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत होना भी आवश्यक है।

वर्ष 2019-20 से 2022 -23 तक प्रदेश की 5,062 छात्राओं को 4,414.25 लाख रुपये की राशि व्यय कर इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2019 20 में 1,239 छात्राओं को 1017.85 लाख की राशि से, वर्ष 2020-21 में 1016 छात्राओं को 945.40 लाख की राशि से, वर्ष 2021-22 में 1,691 छात्राओं को 1,521 लाख की राशि से तथा वर्ष 2022-23 में 1,116 छात्राओं को 930 लाख रुपये की राशि से ये पुरस्कार दिए गए।

योजना के अंतर्गत पुरस्कार की राशि शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, से आवेदन पत्र प्राप्त एवं प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन के साथ परीक्षा अंकतालिका की प्रति, जन आधार कार्ड, नियमित रूप से अध्ययनरत का प्रमाण-पत्र एवं जाति/श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित संस्था प्रधान अथवा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) से संपर्क किया जा सकता है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के संस्थान

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जयपुर

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

कोटा विश्वविद्यालय

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं
आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय, बीकानेर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रदान किए जा रहे हैं बालिका शिक्षा के समुचित अवसर

बालिका शिक्षा से हो रहा उजियारा

■ गजाधर भरत
जनसंपर्क अधिकारी

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके तहत बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बालिकाओं के लिए उनके नजदीकी क्षेत्र में आदर्श, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। बालिकाओं को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य में बालिकाओं को कक्षा एक से माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें मानसिक व सामाजिक रूप से तो प्रेरित किया जाता ही है, साथ ही आर्थिक सहयोग, स्कॉलरशिप व किताबें, पोशाक, आवासीय स्कूल की सुविधा, विद्यालय आवागमन के लिए स्कूटी तथा अन्य जरूरी सहायता प्रदान कर शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के परिणामों को बढ़ाने, विद्यालयों में सोशल और जेंडर गैप को कम करने, सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन जैसे बिंदुओं को लक्षित कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बालिकाएं शिक्षा के अवसरों का समुचित लाभ उठाएं इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई योजनाए चलाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किये हो, एक बीपीएल श्रेणी एवं एक अनाथ बालिका अर्थात प्रत्येक जिले से चार बालिकाएं (न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक) मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए पात्र हैं। वर्ष 2018-19 से एक अनाथ बालिका को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण हेतु एक लाख 15 हजार रुपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2 लाख 25 हजार रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना

इस योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त

करने वाली बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरांत विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का पूर्ण व्यय (प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख अधिकतम 3 वर्ष तक) बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है।

गार्गी पुरस्कार /बालिका प्रोत्साहन प्रमाणपत्र

गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के प्रमाण-पत्र बालिकाओं को सुगमता से प्रदान किए जाने के मद्देनजर उक्त प्रमाण-पत्र शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन उपलब्ध करवाए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करवाई जा रही है।

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में वर्ष 2019-20 से इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा-8, कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की परीक्षा में (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) अन्य पिछड़ा वर्ग, (4) अल्पसंख्यक (5) निःशक्त, (6) सामान्य वर्ग, (7) विशेष पिछड़ा वर्ग एवं (8) बीपीएल वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर पुरस्कार वितरित किया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में भी इन वर्गों में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिये जायेंगे।

आपकी बेटी योजना

यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा- 1 से 8 की बालिकाओं को 2,100 रुपये तथा 9 से 12 तक की बालिका को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार

इस योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उन्हें 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है।

मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार

इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं दृष्टिदोष वाले विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

केजीबीवी विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम वास स्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नहीं जा सकीं अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों के साथ निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान सत्र 2020-21 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 319 केजीबीवी में लक्ष्य 38,850 बालिकाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 34,646 बालिकाएं नामांकित हैं।

केजीबीवी में बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा भोजन एवं सुरक्षित आवास व्यवस्था दी जाती है। उन्हें पुस्तक के शिक्षण सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी दी जाती हैं। इसके साथ ही प्रतिमाह 150 रुपये स्टाइपेंड राशि भी दी जाती है।

बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2020-21

बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2020-21 के तहत जीवन कौशल विकास एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इसमें मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल लर्निंग कौशल के साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण/ मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) गत सत्रों से संचालित है। इसके लिए राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण, जेंडर, सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर भी बालिकाओं में जागरूकता लाई जा सके। इसी प्रकार राज्य में किशोरी शैक्षिक उत्सव भी मनाया जाता है।

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23

समाज को समग्र रूप से विकसित करने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 शुरू की गई, जिसमें दूरस्था शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के निश्चित रूप से दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। बालिकाओं के लिए, शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक स्वतंत्रता और सीखने व योग्यता के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होना है। दूरस्थ शिक्षा द्वारा जिन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, उनमें न केवल भौगोलिक दूरी, बल्कि अन्य सीमित परिस्थितियां भी शामिल हैं, जैसे व्यक्तिगत बाधाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी।

दूरस्थ शिक्षा उन बालिकाओं की जरूरतों को पूरा कर सकती है जो ऑन-कैंपस कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। यह राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने बजट, 2022 में लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना की घोषणा उन लड़कियों और महिलाओं को प्रदान करने के लिए की है जो परिवार और अन्य कारणों से नियमित रूप से कॉलेज या विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाती हैं। इस योजना

के तहत यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स आदि की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

शिक्षा सेतु योजना

समाज में जो बालिकाएं पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य कई कारणों से नियमित विद्यालय से ड्रॉपआउट हो जाती हैं उन बालिकाओं को तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ समन्वय से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत शिक्षा सेतु योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में आवेदन संबंधित समस्त कार्यवाही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा चिन्हित विद्यालयों में परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाती है। शिक्षा सेतु योजना अंतर्गत 2020-21 में 78,478 बालिकाएं एवं महिलाएं पंजीकृत हुईं। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 57,714 बालिकाएं एवं महिलाएं पंजीकृत हुईं। वर्ष 2022-23 में 68,411 बालिका एवं महिलाएं पंजीकृत हुईं। शिक्षा सेतु योजना अंतर्गत अब तक 2,04,603 महिला एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली कालीबाई की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा।

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की गई है।

राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राज्य में संचालित की जा रही है।

यह योजना 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। योजना के अंतर्गत स्कूटी के साथ छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय, एक वर्ष का सामान्य बीमा, पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार), एक हेलमेट दिया जाता है।

विभिन्न विभागों के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु) द्वारा प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1,690 स्कूटी दी जाती हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में 1,000 स्कूटी दी जाती हैं।

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में 6,000 स्कूटी (1,000 सेकंडरी उत्तीर्ण, 5,000 सीनियर सेकंडरी उत्तीर्ण) दी जाती हैं, जिसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिए आरक्षित है।

सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में 600 स्कूटी दी जाती हैं।

अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में 750 स्कूटी दी जाती हैं।

योजना के क्रियान्वयन के संबंध नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 5 जातियों, यथा 1.

बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रेबारी (देबासी, देवासी), 5. गडरिया (गाडरी), गायरी की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सेकंडरी) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हों, उनको 1,500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाती है। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता एवं शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते हैं, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेंगी। स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।

राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं, उनके द्वारा 12वीं (सीनियर सेकंडरी), जो छात्राएं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं उन्हें स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10 हजार रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पीजी डिग्री प्रवेश वर्ष) में 20 हजार रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं।

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की सीनियर सेकंडरी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होने वाले ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख पचास हजार रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह (10,000 रुपये वार्षिक) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने हेतु संशोधित योजना लागू की गई है। यह योजना वर्ष 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है।

नो बैग डे: बाल प्रतिभाओं को तरासने का प्रयास

■ डॉ. रणवीर सिंह
विशेषाधिकारी शिक्षा

दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे छात्र-छात्राओं को विश्व स्तर पर योगदान देने के लिए नए कौशल और ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की उतनी ही आवश्यकता है। प्रभावी संचार, वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक सोच, जीवन कौशल, समस्या समाधान आदि 21वीं सदी के कौशल यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्र बदलते समय में कामयाब हो सकते हैं। इस पहल में राज्य सरकार एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहती है जहां विद्यार्थी अनुभवात्मक अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से इन कौशलों को प्राप्त कर सकें और अंतर्निहित क्षमताओं और बालकों में छिपी हुई संभावनाओं की उड़ान को पंख दे सकें। बालकों में अपार संभावनाएं निहित हैं केवल उनको समुचित मंच के माध्यम से प्रकट करने के अवसर की ही प्रतीक्षा है।

शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं वरन बालकों का समग्र विकास (Holistic Development) करना है। बालकों में आत्मविश्वास के विकास, शिक्षण को आनंददायी बनाने एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाना चाहिए जिस दिन शिक्षण कार्य नहीं करवाकर अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियां नियोजित तरीके से आयोजित की जाएं एवं बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं और संभावनाओं को उड़ान के लिए समुचित मंच और अवसर प्राप्त हो सके।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थी को विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने और प्रकट करने के लिए समर्थन किया है। राजस्थान ने सामुदायिक बाल सभा, बस्ते का बोझ कम करने, त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को सामूहिक रूप से मनाने, कॅरियर डे आदि नवाचारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इससे प्रत्येक बालक के समग्र विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के मामले में तेजी आई है। राज्य सरकार ने समुदाय, शिक्षक और छात्र के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनके अव्यक्त कौशल की पहचान करने के लिए, सीखने की पारंपरिक शिक्षण विधाओं (Pedagogy) से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।

तीन दशक पहले प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों पर पाठ्यक्रम के भार पर

कहा गया था कि इससे बच्चों को अपनी सहज प्रतिभा को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने व अन्य आनंददायी क्रिया करने के लिए समय नहीं मिलता। पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही जैसे शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। बडी कक्षाएं, भारी भरकम पाठ्यक्रम, बड़ी-बड़ी कठिन पुस्तकें एवं परीक्षाओं के भार तले दबे बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी विकास नहीं हो पाता।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने तथा शिक्षा को आनंददायी बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को सभी राजकीय विद्यालयों मे नो बैग डे लागू करने का दूरगामी निर्णय लिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों पर पढ़ाई का प्रेशर कम करते हुए 21वीं सदी के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। नो बैग डे-शनिवार एक अद्भुत नवाचार है। अभी तक के अभ्यास एवं प्रचलित मान्यता व परंपरा के अनुसार बिना पाठ्य पुस्तकों के सीखने की प्रक्रिया को सतत आनंददायी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नो बैग डे कार्यक्रम को इसके अंतर्निहित भावना के अनुसार व्यवस्थित बनाया गया है। थीम के आधार पर विद्यालयों में साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद, जीवन मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास संबंधी कार्यक्रम, प्रार्थना सभा, बाल सभाएं, प्रोजेक्ट वर्क तथा अन्य विविध क्रियाएं आयोजित की जाती है नो बैग डे शनिवार को प्रभावी एवं आनंददायी अधिगमकारी बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नया सीखने एवं ज्ञान अर्जन की इस प्रक्रिया में विद्यालयों में बेहतर कार्य हो रहे है।

शिक्षा का विस्तार अनंत है। बालक का सर्वांगीण विकास, शिक्षा का प्रथम तथा अंतिम उद्देश्य है। ज्ञान हेतु पुस्तकें महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों अथवा स्कूल के बस्ते में ही नहीं अपितु इनसे बाहर भी है। परिस्थिति, पर्यावरण, दृश्य, ध्वनि, अनुभव और अवलोकन अध्ययन प्रक्रिया में सीखने की सहज प्रक्रिया के प्रभावी चरण हैं। बिना किताब, अध्ययन का कौतूहल, सीखने को और आनंददायी व स्थायी बनाएगा। जानने के साथ पहचानने और ज्ञानोपयोग की सार्थकता करके सीखने में फलदायक होती है। पुस्तकों के साथ—साथ बाहर बिखरे ज्ञान को विद्यार्थी अपने अनुभवों से भी सीखता है। यदि अध्ययन की इस आनंददायी प्रक्रिया के लिए विद्यालय में ही औपचारिक समय निर्धारित हो, जिससे वह अपने ज्ञानार्जन के लिए परिस्थितियों, क्रिया विधियों, गतिविधियों और मानसिक व शारीरिक मंथन करे, तो ऐसा ज्ञान विद्यार्थी के मस्तिष्क में न केवल स्थायी होगा बल्कि ज्ञान उपयोग के दृष्टिकोण से यह फलदायक भी होगा। बाल मनोविज्ञान की इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2020 में विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों के लिए नो बैग डे घोषित किया। प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में विद्यार्थी अपना स्कूल बैग नहीं लाएंगे और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अपने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखेंगे। यह गतिविधियां क्या हों? कैसे की जानी है? कौन-कौन सी गतिविधियां पुस्तकों से बाहर स्थानीय वातावरण में मिल सकती हैं? शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान के खजाने से बालकों के लिए उनसे अवधारणा आधारित गतिविधियों का आयोजन करवाकर शनिवार को राज्य सरकार की आनंददायी अध्ययन तथा अधिगम की इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं।

अवधारणा

हर महीने के प्रत्येक शनिवार को अलग-अलग अवधारणाएं आधारित विनिश्चय की गई गतिविधियों का आयोजन कर बालकों को शिक्षणेत्तर अनुभव साझा कर उनके अंदर की प्रतिभा को प्रकट करने एवं नेतृत्व कौशल के विकास का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

पहला शनिवार - राजस्थान को पहचानो

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए राजस्थान के भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति से परिचित करवाने के लिए प्रश्नोत्तरी, प्रोजेक्ट कार्य, सर्वे कार्य एवं अन्य समसामयिक गतिविधियां आयोजित होती हैं।

दूसरा शनिवार - भाषा कौशल विकास एवं मूल्यपरक शिक्षा

विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए अंतर्सदन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस प्रतियोगिता में अक्षरों से अधिकाधिक शब्द निर्माण, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं अन्य प्रचलित भाषाओं में वाद-विवाद, कविता पाठ, निबंध लेखन, संक्षिप्तीकरण, चित्र से कहानी विकसित करना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करना आदि गतिविधियों का आयोजन होता है।

तीसरा शनिवार - खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए बालकों में शारीरिक सौष्ठव, मानसिक दृढ़ता, सह-अस्तित्व का विकास, दल भावना से कार्य करने के कौशल का विकास, नेतृत्व कौशल का विकास, निरोगी राजस्थान, परंपरागत खेलों को विकसित करने और देश के लिए भावी खिलाड़ी तैयार करने के लिए योजनाबद्ध गतिविधियों का आयोजन होता है। सामान्य नागरिक जीवन में यातायात नियमों के प्रति सजगता, और पालन करने के लिए बड़ों को भी सजग करने की सहज प्रवृत्ति का विकास होता है। बालिकाएं गुड टच बैड टच के बारे में सहजता से सीख रही हैं।

चौथा शनिवार - मैं भी हूं वैज्ञानिक : वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए बालकों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने, स्वयं करके सीखने एवं प्रमाणित करने के लिए कौशल विकास हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को घटनाओं को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखने एवं जीवन में आने वाले प्रत्येक पहलू का अन्वेषणात्मक पक्ष जानने का अवसर खेल—खेल में मिल रहा है।

पांचवां शनिवार - बाल सभा - मेरे अपनों के साथ

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों में नैसर्गिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रकृति से प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, मूल्यपरक (Value Education) जीवन-कौशल शिक्षा के लिए कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर बालकों को क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए बालसभा में सामुदायिक मंच उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद अभिभावक-शिक्षक बैठक (Parent-Teacher Meeting—PTM) का आयोजन किया जा रहा है। अभिभावक बालकों की क्षमताओं से पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं और उनको कम करके आंकते हैं। बाल सभा के माध्यम से अभिभावक उनके बच्चों की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे है।

राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल का क्रियान्वयन समुचित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए एक राज्यव्यापी समान पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। वर्ष के दौरान आने वाले प्रत्येक शनिवार के लिए गतिविधियों का तारतम्य स्थापित करते हुए उद्देश्यपरक पाठ्यक्रम ही नहीं वरन शिक्षा अधिकारियों, संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की प्रतिबद्धता भी अपेक्षित है।

विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनके अव्यक्त कौशल की पहचान करने के लिए, सीखने की पारंपरिक शिक्षण विधाओं (Pedagogy) से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को कई रुचिकर गतिविधियों में शामिल किया जाकर जो आत्म-जागरूकता, पारस्परिक कौशल और उनके बीच सामाजिक जिम्मेदारी की भावना एवं नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते है। इसके लिए सीखने के प्रतिफल निर्धारित कर अवधारणा आधारित गतिविधियों का सृजन स्थानीय परिस्थितियों एवं परिवेश के अनुसार किया जाता है।

नो बैग डे गतिविधि "खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान" के तहत शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला की पहल पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर "चैस इन स्कूल एक्टीविटी" आयोजित की गई, जिसमें पूरे राज्य के 38 लाख 21 हजार 9 विद्यार्थियों ने भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

राजस्थान अपने 67,465 स्कूलों के साथ इस मॉडल के आधार पर धरातल पर कार्य कर रहा है, जहां बालकों के व्यक्तित्व विकास में "नो बैग डे : संभावनाओं की उड़ान" नवाचार का प्रभाव बड़े पैमाने पर परिलक्षित हो रहा है।

नवाचारों से संवर रहा भविष्य

■ डॉ. सूरज सिंह नेगी
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले में शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं प्रभावी रुप से क्रियान्वित की जा रही हैं और इनका सार्थक परिणाम भी नजर आ रहा है। जिला प्रशासन भी विभिन्न नवाचारों के जरिये शिक्षा के उत्थान और युवाओं में रचनात्मक कौशल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

भविष्य की उड़ान से बदल रहा भविष्य

जिले के लिंगानुपात एवं महिला साक्षरता की स्थिति सुधार में शिक्षा की भूमिका को महत्व देते हुए बेटियों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 5 अप्रैल 2022 को 'भविष्य की उड़ान' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके तहत राज्य सरकार की मंशा अनुरूप विद्यार्थियों विशेषतः बालिकाओं के लिए सुंदर परिसर, स्वच्छ शौचालय, कॅरियर काउंसलिंग एवं निःशुल्क लाइब्रेरी उपलब्ध करवाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के जरिए सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है।

कॅरियर काउंसलिंग और मॉक टेस्ट से मिल रही दिशा

महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए राजकीय सेवाओं में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों, विभिन्न अकादमिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं में कॅरियर को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए उपखंड स्तर पर कॅरियर गाइडेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इनमें विषय विशेषज्ञों द्वारा पुस्तकालयों के अधिकतम सदुपयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी के सकारात्मक प्रयोग, उचित कॅरियर निर्धारण, सफलता के लिए सही दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में कॅरियर काउंसलिंग की गई। परीक्षाओं से पूर्व मॉक टेस्ट आयोजित किए गए जिसमें 3,000 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। विद्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार लाने हेतु कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 3 बार प्री बोर्ड परीक्षा ली गई एवं कमजोर विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की गई।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों के सुखद परिणाम के रूप में इस वर्ष सवाई माधोपुर जिला 12वीं वाणिज्य में शत-प्रतिशत परिणाम के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं 12वीं साइंस में गत वर्ष से सुधार करते हुए 94.14 प्रतिशत परिणाम के साथ दसवें स्थान पर आ गया है। शिक्षकों द्वारा ड्रॉप आउट बालिकाओं के परिजनों को घर-घर जाकर समझाया जा रहा है जिससे गत सत्र की तुलना में बालिकाओं के ड्रॉपआउट में गिरावट आई तथा पुनः प्रवेश दर में वृद्धि हुई है।

निःशुल्क लाइब्रेरी

भविष्य की उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत जिन महिलाओं के पास घर में पढ़ने की सुविधा या माहौल नहीं है, उन्हें अध्ययन का बेहतर माहौल देने, महिलाओं की राजकीय सेवाओं में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने, उच्च शिक्षा एवं बोर्ड

की परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए अध्ययन करने हेतु सभी उपखंड स्तर पर 20 नि:शुल्क पुस्तकालयों की सुविधा दी जा रही है। इन पुस्तकालयों में फर्नीचर, शीतल पेयजल, पंखे कूलर, पत्र—पत्रिकाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु उच्चस्तरीय पुस्तकें, विभिन्न नोट्स, प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक बालिकाओं को पुस्तकालय से जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को लाइब्रेरी में अध्ययन हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे जिले की बालिकाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा।

आंगनबाड़ी नन्हे-मुन्नों के सीखने का माध्यम भी

आंगनबाड़ी केंद्रों को बेटियों के पोषण एवं शैक्षणिक विकास का माध्यम मानते हुए उनके भौतिक विकास के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों एवं भामाशाहों को प्रेरित कर उनका भी कायाकल्प किया गया है। महिलाओं व युवतियों को एनीमिया के बारे में जागरूक करने के लिए सवाई माधोपुर में लाल क्रांति कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विभिन्न स्तर पर किए गए प्रयासों से यहां के 200 से अधिक आंगनबाड़ियों की रंगत बदल गई है। यहां अध्ययनरत नन्हे-मुन्ने आंगनबाड़ी की दीवारों पर चित्रित वर्णमाला, अंग्रेजी के अल्फाबेट, गिनती, पहाड़े, जानवरों, फलों आदि से खेल-खेल में ज्ञानार्जन करते हैं। नन्हे-मुन्ने विजुअल्स की मदद से ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। खेल के माध्यम से सीखने की सुविधा के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर एवं खिलौना बैंक स्थापित किए गए हैं।

क्राउडफंडिंग से राजकीय स्कूलों का हो रहा कायाकल्प

जिला प्रशासन की मुहिम को जिले के सभी अधिकारी—कर्मचारी, सामाजिक संगठन, जन प्रतिनिधि, धर्मगुरु अपना योगदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम से मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीति पर खर्च होने वाली राशि, सरसों की तूड़ी बेचकर होने वाले भंडारे, सेवानिवृत्ति, पुण्यतिथि, जन्मदिन, शादी की सालगिरह के अवसर पर होने वाले खर्च में से बचाकर विद्यालय विकास के लिए लगाने से शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। भामाशाह से प्राप्त राशि का उपयोग कर स्कूलों में आधारभूत संरचना, सौंदर्यीकरण, आईसीटी लैब, सीसीटीवी कैमरे, पुस्तकालय, फर्नीचर, पेयजल सुविधा, खेल सामग्री, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय के निर्माण आदि करने से स्कूल की तस्वीर बदल रही है।

जिले की सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, जन सहयोग आदि के माध्यम से पिछले 1 साल में 15 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई है।

बोर्ड तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं एवं सरकारी स्कूलों के विकास में आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं को बढ़ावा देने एवं प्रेरित करने के लिए समय-समय पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाता है तथा स्कूल में शिलापट्ट पर उनकी सूची लगाई जाती है ताकि उनमें गर्व की भावना पैदा हो। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पादरी तोपखाना खंडार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीनापुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसाली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा सहित कई विद्यालयों में भामाशाह द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई। साथ ही बनोटा, भूरी पहाड़ी, डेकवा, नींदड़दा, सहित कई अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भामाशाह द्वारा भवन निर्माण कार्य करवाया गया है।

'भविष्य की उड़ान' से एक तस्वीर बदल रही है। तूड़ी के दान से स्कूल भवन बन रहे हैं। स्कूलों की दीवारें अब नए रंग में रंग रही हैं। मृत्युभोज कुरीति अब शिक्षा दान में बदल रही है। लाइब्रेरी में जाकर बालिकाएं पढ़ रही हैं और अपने सुखद भविष्य का निर्माण कर रही हैं।

स्कूली बच्चों की अभिव्यक्ति के निखार के लिए पाती लेखन

मानव जीवन में संदेशों का विशेष महत्व है। एक दौर था जब अपनों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम पत्र हुआ करते थे, लेकिन आधुनिक संचार के प्रसार ने पत्र लेखन को जैसे लुप्त कर दिया है। अब अपनों को संदेश पहुंचाने की बात हो या

किसी खास अवसर पर आमंत्रित करना सब सोशल मीडिया के माध्यम से ही होने लगा है। इन सबके बीच सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन आने वाली पीढ़ी को बुजुर्गों, समाज, राष्ट्र,मानवता के प्रति संवेदनशील बनाने, युवाओं में मानवीय मूल्यों को जाग्रत करने एवं एक-दूसरे की भावनाओं का संप्रेषण करने के रचनात्मक साधन पत्र लेखन विधा पर काम कर रहा है।

पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन

विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर अब तक अखिल भारतीय स्तर की उन्नीस पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें गुरु की पाती शिष्य को, पिता की पाती संतान को, मां की पाती बेटी को, शिष्य की पाती गुरु को, संतान की पाती माता-पिता को, पत्र बच्चों के, कोरोना को कैसे हराएं, बाल विवाह को रोकें, जल संरक्षण, मित्र को पत्र, एक पाती दादा-दादी, नाना-नानी की यादों के नाम, प्रकृति की पाती मानव को, शिक्षक को पत्र, बापू की पाती मेरे नाम, माटी की पाती मेरे नाम, पाती डाकिए को, बिटिया की पाती बाबुल को, लिख दूं पाती यादों के गलियारे से आदि शामिल हैं। आज देशभर के 22 राज्यों एवं नौ राष्ट्रों से प्रतिभागी पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लेकर इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब तक दस हजार से अधिक पत्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त हो चुके हैं।

स्कूली बच्चों में बढ़ रहा है क्रेज

पत्र -लेखन के लिए केवल युवा, प्रौढ़ एवं बुजुर्ग ही उत्साहित नहीं हो रहे हैं, अपितु स्कूली बच्चों के मध्य पत्र लेखन की जबरदस्त उत्सुकता देखी गई है। हाल में आयोजित 'बिटिया की पाती बाबुल के नाम' अखिल भारतीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में देश भर के 189 स्कूलों से 8,000 से भी अधिक स्कूली बालिकाओं ने पत्र लिख भिजवाए।

प्राप्त पत्रों में से अंतिम रूप से चयनित 181 पत्रों के संकलन से 'लिख दी पाती बाबुल को' पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। इससे पहले 1,500 स्कूली बच्चों ने अपने अभिभावकों को पत्र लिखे थे जिसमें से 91 पत्रों का चयन कर 'बच्चों के पत्र' शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित करवाई गई। इन पत्र लेखन प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चे बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

चयनित पत्रों का पुस्तक रूप में संकलन

पत्र लेखन प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों के पत्रों में से विद्वान निर्णायकों के निर्णय के बाद अंतिम रूप से चयनित पत्रों को पुरुस्कार भी दिया जाता है। अब तक पत्र आधारित निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं :

1. मां की पाती बेटी को, 2. पत्र पिता के, 3. बच्चों के पत्र, 4. एक पाती मीत को , 5. प्रकृति की पुकार, 6. शिक्षक को पत्र, 7. बाबू की चिट्ठी, 8. माटी की पुकार, 9. पाती स्मृतियों के झरोखे से, 10. पाती डाकिए को, 11. लिख दी पाती बाबुल को आदि। इस मुहिम से इस बात की स्वीकार्यता बढ़ी है कि मौजूदा परिवेश में सामाजिक सरोकार एवं संवेदनाओं को जाग्रत करने में पत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं। मुहिम का असर कुछ ऐसे दिखाई देने लगा है :

- लोग एक-दूसरे को पत्र लिखकर अपने समाचार साझा करने लगे हैं।
- पत्र लेखन से जुड़े स्कूली बच्चों की लेखन शैली में जबरदस्त सुधार हुआ है।
- एक-दूसरे को किसी खास अवसर पर महंगे उपहार की बजाय पत्र देने का चलन बढ़ रहा है।
- देशभर के कई स्कूल, हॉस्टल में नियमित रूप से पत्र आधारित पुस्तकों में से किसी एक पत्र को वाचन होने लगा है।
- इसी प्रकार कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत युवाओं को तनाव के दौरान किसी अपने को पत्र लेखन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- बरसों से संवादहीनता की स्थिति को भी पत्र लिखकर दूर किया जाने लगा है।
- रिश्तों की अहमियत समझ में आने लगी है।

इस तरह आज के दौर में पत्र लेखक विधा न केवल अपनो को एक-दूसरे के करीब लाने का माध्यम है, अपितु स्कूली बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों में भी इजाफा करने में कारगर साधन सिद्ध हो सकता है।•

ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को साकार करते शिक्षा विभाग के कार्मिक

■ हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

महात्मा गांधी का मानना था कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार है। शेष संपत्ति का एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल करने के साथ उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। महात्मा गांधी के इन विचारों का अनुसरण आज भी अनेक लोग करते हैं।

शिक्षक ने विद्यालय हित में किया अपनी संपति का उपयोग

बीकानेर में शिक्षक श्री रामेश्वर चौधरी ने ट्रस्टीशिप की भावना से अपनी संपति का उपयोग विद्यालय और विद्यार्थी हित में किया। वर्ष 2000 में उनके पिता श्री लाखाराम चौधरी का निधन हो गया। समाज और परिवार को संदेश देते हुए श्री चौधरी ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत मृत्युभोज पर व्यय होने वाली राशि से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूंडसर में दो कमरे और बरामदे बनवाए, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। श्री चौधरी ने इसे दोहराते हुए वर्ष 2020 में अपनी माताजी श्रीमती जड़ाव देवी की स्मृति में भी दो कमरे और बरामदे बनवाए। इन दोनों अवसरों पर उन्होंने अपने पांच से छह महीनों की तनख्वाह के बराबर राशि व्यय की। इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत नया स्कूल भवन बनवाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने जन सहयोग से 20 लाख रुपये एकत्रित किए। इसमें दो लाख रुपये का सहयोग उनके परिवार द्वारा भी किया गया। योजना के तहत 40 प्रतिशत राशि जनसहयोग से एकत्रित होने के पश्चात् शेष साठ प्रतिशत कुल 30 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा योजना मद से स्वीकृत कर दिए गए। इस प्रकार 50 लाख रुपये एकत्रित होने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया प्रगतिरत है। चौधरी पिछले साल सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनकी भावनाएं इस स्कूल से जुड़ी होने के कारण लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं।

सहायक कर्मचारी ने पेश की मिसाल

बीकानेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नत्थूसर बास की सहायक कर्मचारी श्रीमती विमला मारू ने अपनी जमा पूंजी में से लगभग साढे छह लाख व्यय करते हुए स्कूल के लिए दो कक्षा कक्ष बनवाए। अपने पति को खो चुकी श्रीमती मारू का मानना है कि भावी पीढ़ी के बच्चों के लिए सरकार के प्रयास भरपूर हो रहे हैं। 'पे बैक टू सोसायटी' की भावना के साथ वह समाज के लिए अपना भी योगदान देना चाहती है। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गत दिनों स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान श्रीमती विमला मारू का सम्मान करते हुए उसकी हौसला अफजाई की और इस पहल को दूसरों के लिए प्रेरणादायी बताया और कहा कि श्रीमती विमला मारू ने सबसे अंतिम पंक्ति की राजकीय कर्मचारी होने के बावजूद स्कूल में दो कक्षा कक्ष बनवाए हैं। इन पर साढ़े छह लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह राशि इन्होंने ही दी है। निःसंदेह यह पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है।

अपने वेतन से कराया विद्यालय में निर्माण कार्य

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक राजकीय सेवा के साथ सामाजिक सेवा भी करते हैं। राजकीय विद्यालयों में ऐसे बहुत से अध्यापक और

अध्यापिकाएं हैं जो विद्यालयों में अपने वेतन से निर्माण कार्य कराने के साथ गरीब बच्चों और उनके परिवारों की मदद करते हैं। भरतपुर जिले की उच्चैन तहसील के गांव फतेहपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती प्रतिभा शर्मा ने अपने गांव मंगतासर के विद्यालय में अपने वेतन से मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना कराई। इस विद्यालय परिसर में सिकंदरा से निर्मित मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की। इस विद्यालय के निर्माण से लेकर अब तक किसी अध्यापक द्वारा अपने वेतन से विद्यालय में यह पहला निर्माण कार्य है। इसके अलावा श्रीमती प्रतिभा शर्मा ने गांव की गरीब महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए अपने वेतन से सिलाई मशीनें खरीदकर वितरित कीं। मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत श्रीमती शर्मा गरीब बच्चों को आवश्यक सामग्री भी समय-समय पर अपने वेतन से उपलब्ध कराती हैं।

भरतपुर जिले के नदबई तहसील में गांव बरोलीरान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री राकेश कुमार मिश्र ने अपने वेतन से 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि से विद्यालय में शौचालयों का निर्माण कराया। श्री मिश्र ने सेवानिवृत्ति के मौके पर शौचालयों का निर्माण कर विद्यालयों को समर्पित किये। विद्यालय में शौचालयों के अभाव में छात्र-छात्राओं को परेशानी होती थी। शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकाएं भी भामाशाह की भूमिका निभाकर विद्यालय के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण राज्य के प्रत्येक जिले में मिल जाते हैं।

रेबारियों की ढाणी का हाईटेक प्राथमिक विद्यालय

उदयपुर जिले के बड़गांव ब्लॉक में इसवाल गांव के निकट पहाड़ी तलहटी में रेबारियों की ढाणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पुष्पकांत व्यास सहित शिक्षकों का जज्बा देखते ही बनता है। विद्यालय के लिए कुछ कर गुजरने के उनके जज्बे के कारण जन सहयोग एवं स्थानीय स्टाफ के प्रयासों से विद्यालय की तस्वीर ही बदल दी है।

शिक्षा के लिए तकनीक और नवाचारों का सहारा लेने वाले इस स्कूल में स्मार्ट क्लास सजती है तो बच्चे पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई में जुट जाते हैं। स्कूल में स्मार्ट क्लास के तहत प्रोजेक्टर व कंप्यूटर उपलब्ध हैं तो विद्यालय में अनुशासन व सुरक्षा के लिए संपूर्ण भवन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

विद्यालय में नियमित साफ-सफाई, आकर्षक फूलदार पौधे, बरामदे से लेकर दीवारों पर महापुरुषों की जीवनियों और होनहार बालकों की तस्वीरें देखकर यह कल्पना नहीं कर सकते कि यह राजकीय विद्यालय का भवन है। श्री व्यास के प्रयासों से विद्यालय का निखरा स्वरूप हर किसी को इस ओर आकर्षित करता प्रतीत होता है।

इस विद्यालय का सिर्फ भौतिक स्वरूप ही आकर्षक नहीं है अपितु इसमें अध्ययनरत विद्यार्थी भी बड़े मेधावी और सृजनधर्मी हैं। ये विद्यार्थी चुटकियों में कहानी एवं कविताएं रच देते हैं। प्रतिभाओं को तराशने में शिक्षकों की अहम भूमिका है जो उबड़-खाबड़ रास्ते से गांव के बीच से होकर इस विद्यालय तक पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

इसका परिणाम यह है कि विद्यालय की सूरत और यहां की बाल प्रतिभाएं निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ रही हैं। अध्ययन के साथ ही इस विद्यालय के बच्चे साहित्य और कला में इसने पारंगत हैं कि इन्हें केवल एक शब्द देने पर ये चुटकियों में आपको कहानी और कविता की रचना कर सुना देते हैं।

शिक्षकों की मेहनत से इस विद्यालय से पिछले 5 सालों में 8वीं बोर्ड में अच्छे प्रतिशत लाकर 5 बच्चे जिला स्तर पर लेपटॉप जीत चुके हैं। 176 बच्चों के नामांकन पर 8 शिक्षक एवं एक प्रधानाध्यापक लगे हुए हैं। इस विद्यालय में विद्यालय प्रशासन ने ग्रामीणों और भामाशाहों की मदद से कंप्यूटर लैब बना दी हैं। बच्चों के क्लास रूम में फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे, प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, अनाउंसमेंट के लिए माइक लगे हुए हैं।

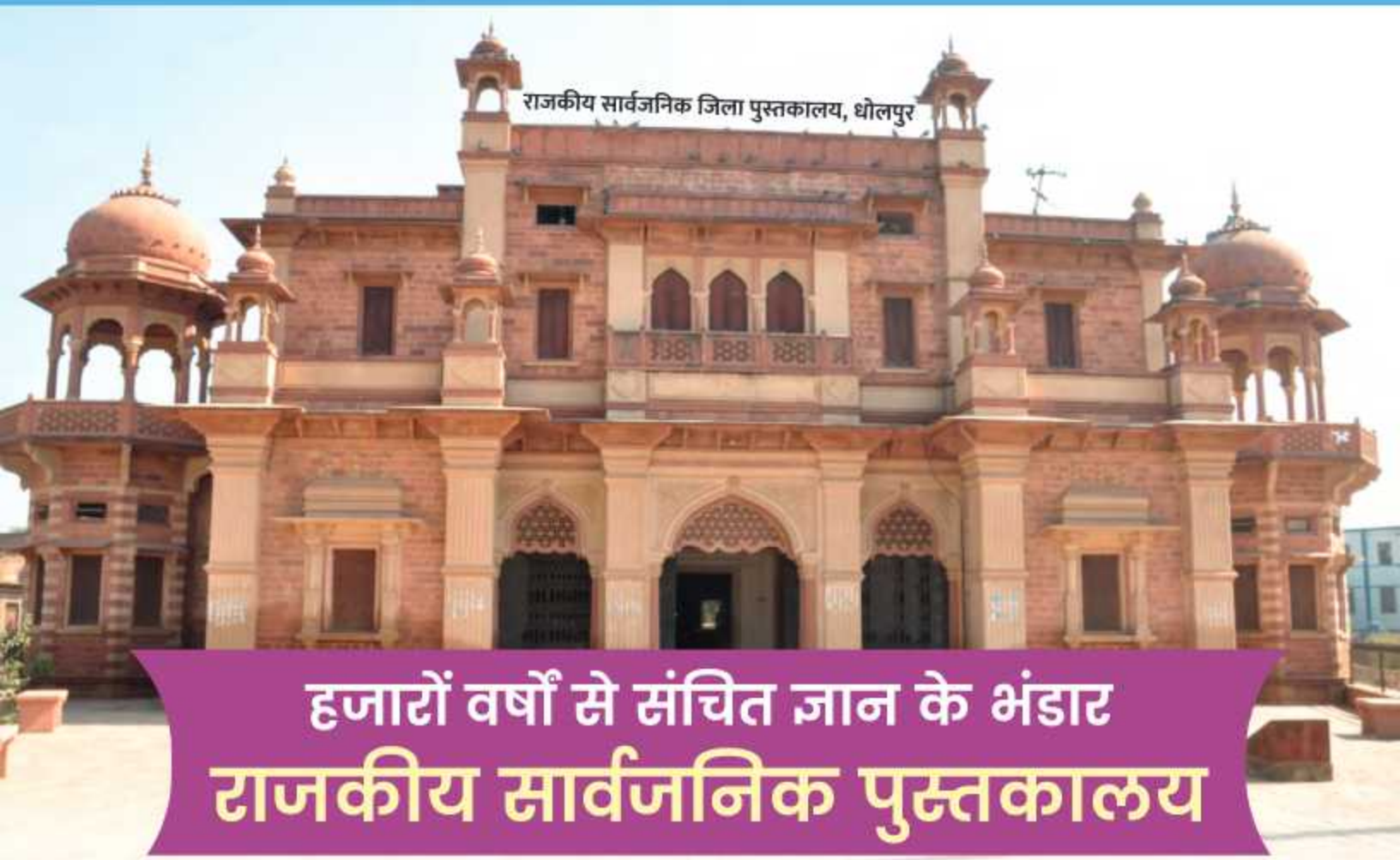

राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, धोलपुर

हजारों वर्षों से संचित ज्ञान के भंडार
राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय

■ रजनी सी. सिंह
निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

पुस्तकालयों में तरह-तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। ये ज्ञान के ऐसे भंडार हैं जहां हम हजारों वर्षों से संचित ज्ञान और दुनिया के तमाम कोने में स्थित सर्वश्रेष्ठ दिमागों की लेखनी से रूबरू होते हैं। पुस्तकालय में विद्यार्थियों को अपने समय का सही उपयोग, एकांत वातावरण, ध्यान चित विषयों को सही और समझ से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। पुस्तकालय में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और आधुनिक समय के अनेक डिजिटल संसाधन भी मिलते हैं।

राज्य सरकार पुस्तक प्रेमियों के लिए विभिन्न तरह की सहूलियतों के साथ अनेक स्तर पर पुस्तकालयों का संचालन कर रही है।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य करता है। वर्तमान में कुल 323 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय (राज्य केंद्रीय पुस्तकालय—1, मंडल पुस्तकालय-7, जिला पुस्तकालय-33, पूर्णकालिक पंचायत समिति पुस्तकालय-6 एवं पंचायत समिति पुस्तकालय (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 276)) संचालित हैं। इनमें से 47 सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में संचालित 276 सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के अधीन है। इन 276 पुस्तकालयों को विभाग द्वारा आधारभूत संरचना यथा भवन, फर्नीचर तथा पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

डॉ. राधाकृष्णन् राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जयपुर

इस पुस्तकालय की स्थापना 15 अगस्त, 1956 को हुई थी। इसे वर्ष 1990 में सौम्य मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी नगर, जयपुर स्थित भवन में स्थानान्तरित किया गया। पुस्तकालय में धर्म-दर्शन, समाज-विज्ञान, मानविकी, तकनीकी, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू आदि भाषाओं में साहित्य, इतिहास, जीवनियां आदि का पर्याप्त संग्रह है। पुस्तकालय में लगभग 1,16,873 पुस्तकों का भंडार होने के साथ-साथ विश्वकोश, शब्दकोश, तकनीकी शब्दावली, गजेटियर्स, वार्षिकी निर्देशिका, चित्रावली, जिल्द प्रतिवेदन एवं सी.डी.आदि भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के विशाल वातानुकूलित वाचनालय कक्ष में हिंदी, अंग्रेजी भाषा में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक आदि आवृत्ति की 90 प्रमुख पत्रिकाएं तथा हिंदी व अंग्रेजी भाषा के 23 प्रमुख राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों के अध्ययन की

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, उदयपुर

सुविधा भी प्रदान की जाती है। पुस्तकालय में बालकक्ष वातानुकूलित है, जिसमें 5 से 14 वर्ष की आयु के बालक एवं बालिकाओं हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की सभी विधाओं में लगभग 17,198 पुस्तकें उपलब्ध हैं। बाल कक्ष में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के प्रमुख प्रकाशनों के बाल साहित्य का पर्याप्त संग्रह है। पुस्तकालय में पृथक् से वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, संदर्भ कक्ष, फोटोकॉपी सुविधा, पुराने समाचार पत्रों के संग्रहण के साथ-साथ पुस्तकालय में सेमिनार, मीटिंग आदि हेतु सशुल्क वातानुकूलित सभा कक्ष भी उपलब्ध है।

राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, जयपुर

यह जयपुर का पहला पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को महाराजा मानसिंह द्वारा सन् 1652 में आमेर में स्थापित किया गया था। पुस्तकालय में महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1704 में 76 ग्रंथ, वर्ष 1711 में 420 ग्रंथ व वर्ष 1716 में 336 ग्रंथों की वृद्धि की तथा इसे आमेर से नई राजधानी जयपुर के जलेब चौक में स्थापित किया गया। वर्ष 1866 में इस पुस्तकालय को अपनी निजी ग्रंथालय सीमा से निकालकर सार्वजनिक उपयोग हेतु महाराजा सार्वजनिक ग्रंथालय के नाम से स्थापित किया गया। वर्तमान में जिस भवन में यह पुस्तकालय संचालित है, उसकी स्थापना वर्ष 1886 में हुई थी। पुस्तकालय में लगभग 30 हजार संदर्भ ग्रंथ एवं 108 दुर्लभ ग्रंथ व 333 हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय में अबुल फजल द्वारा उर्दू में अनुवादित महाभारत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1860 से भारत व अन्य देशों के कतिपय दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को भी यहां देखा जा सकता है। इस पुस्तकालय का सूची पत्र वर्ष 1930 में ही मुद्रित हो गया था।

यह सूची पत्र लंदन के कैंब्रिज व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में आज भी उपलब्ध है। पुस्तकालय में लगभग 1,36,833 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं। पुस्तकालय में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिकीकरण का कार्य किया गया, जिसमें पुस्तकालय में उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकों का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन किया गया तथा पुस्तकालय के सुगम संचालन हेतु पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड कर पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कोहा एवं आर.एफ.आई.डी. तकनीक स्थापित की गई।

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, अजमेर

इस पुस्तकालय की स्थापना 15 सितंबर, 1997 को हुई। पुस्तकालय रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस स्टैंड के मध्य वीर कुमार मार्ग पर स्थित है। इस पुस्तकालय में दर्शन, धर्म, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी, इतिहास, साहित्य आदि से संबंधित लगभग 33,248 पुस्तकों का संग्रह है। पुस्तकालय के वाचनालय में पाठकों हेतु 107 पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं।

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, बीकानेर

वर्ष 1937 में स्थापित इस पुस्तकालय को, बीकानेर राज्य के तत्कालीन महाराजा श्री गंगासिंह बहादुर ने अपने निजी पुस्तकालय में संगृहीत बहुमूल्य, दुर्लभ ग्रंथ अपनी राज्य की जनता के अवलोकनार्थ समर्पित किए। यह पुस्तकालय म्यूजियम चौराहा पर स्थित है। पुस्तकालय में संगृहीत भारतीय चित्रकला, देश-विदेश की प्रसिद्ध पेंटिंग की प्लेट, विभिन्न चित्रशैलियों के चित्र, ऐतिहासिक विषय पर विशिष्ट संग्रह, बीकानेर गोल्डन जुबली, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेदों एवं पुराणों की ऋचाएं, ज्योतिष साहित्य के अनूठे संग्रह बरबस ध्यान आकर्षित करते हैं। इस पुस्तकालय में 91,071 पुस्तकों का संग्रह है।

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, कोटा

शुरुआत में इसका संचालन बहादुर बाजार में बापना हवेली से हुआ। इसके बाद वर्ष 1984 में उक्त पुस्तकालय को नगर विकास न्यास परिसर, दादाबाड़ी, कोटा के भवन में स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में पुस्तकालय सी.ए.डी. कॉलोनी परिसर में संचालित है। पुस्तकालय में लगभग 73,456 पुस्तकों सहित 1,542 दुर्लभ ग्रंथ भी उपलब्ध हैं।

राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, जोधपुर

जोधपुर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1 अक्टूबर, 1915 को तत्कालीन महाराजा श्री सुमेर सिंह जी के द्वारा जोधपुर शहर के नागरिकों को पुस्तकालय सेवा का लाभ देने एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सूरसागर में की गई थी। वहां से इस पुस्तकालय को शहर के मध्य राजकीय मुद्रणालय

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, बीकानेर

परिसर में तथा 17 मार्च, 1935 को बस स्टैंड के पास उम्मेद उद्यान में सरदार म्यूजियम के साथ संचालित किया गया। म्यूजियम के विस्तार के कारण 15 अगस्त 2017 को इस पुस्तकालय को अस्थायी रूप से नगर निगम के पुराने भवन सोजती गेट पर स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में यह पुस्तकालय नगर निगम के पुराने भवन में संचालित हो रहा है। इस पुस्तकालय में 89,454 पुस्तकों का संग्रह किया गया है। लगभग 74 पत्र-पत्रिकाएं पाठकों के पढ़ने हेतु मंगवायी जाती हैं। इस पुस्तकालय में अनेक प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रंथ हैं, जिसमें कृष्णागढ़ की तवारीख, जहांगीरनामा, पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख हैं। पुस्तकालय के अधीन दो बाल पुस्तकालय एवं वाचनालय भी संचालित हैं।

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, उदयपुर

यह पुस्तकालय झीलों की नगरी उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। 1887 ई. में महाराणा फतेह सिंह जी ने इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। 12 मार्च, 1951 को यह पुस्तकालय सार्वजनिक घोषित किया गया। इसमें लगभग 89,665 पुस्तकों का संग्रह है। यह पुस्तकालय मुख्यतः पुरातत्त्व एवं इतिहास की पुस्तकों से समृद्ध है। यहां अनुसंधान हेतु राजस्थान से बाहर के अध्येता भी आते हैं।

राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, भरतपुर

यह पुस्तकालय वर्ष 2008 में भरतपुर संभाग मुख्यालय होने के कारण खोला गया है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में 47,087 पुस्तकें उपलब्ध हैं। उक्त पुस्तकालय अटलबंध रोड, सेटेलाइट हॉस्पिटल के सामने, भरतपुर में स्थित है।

दृष्टिबाधितों के लिए पृथक् से कक्ष

डॉ. राधाकृष्णन् राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर एवं सात मंडल पुस्तकालयों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अध्ययन एवं कंप्यूटर उपयोग के लिए पृथक कक्ष स्थापित हैं। वहां ब्रेल, डेजी पुस्तकें एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। उक्त पुस्तकालयों में ब्रेल बुक्स, डेजी बुक्स एवं डेजी बुक्स के उपयोग हेतु डेजी प्लेबैक हार्डवेयर (वाचक) तथा कंप्यूटर उपयोग के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर एनवीडीए लेखा, संगीता (हिंदी और अंग्रेजी स्वर) भी उपलब्ध हैं। स्केन पुस्तक को पढ़ने के लिए एबीबीवाईवाई फाइन रीडर (अंग्रेजी ओसीआर) और देवनागरी (हिंदी ओसीआर) उपलब्ध है। राज्य के 22 जिला पुस्तकालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध है।

सावित्री बाई फुले वाचनालय

अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा हेतु राज्य के 33 जिलों में संचालित जिला पुस्तकालयों में सावित्री बाई फुले वाचनालय स्थापित किए गए हैं। इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्वाध्याय करने वाले युवाओं को आवश्यक प्रतियोगी साहित्य के साथ-साथ कंप्यूटर, प्रिंटर्स, इंटरनेट, फर्नीचर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है।

2500 करोड़ की लागत से बांसवाड़ा जिले की अपर हाईलेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास

■ **अरुण कुमार जोशी**
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 12 जून को बांसवाड़ा के लंकाई (बागीदौरा) में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2,500 करोड़ रुपये की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से जिले की 6 तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।

श्री गहलोत ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की। कैनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे सिंचाई जल सुनिश्चितता के चलते क्षेत्र में सतत रूप से विकास संभव हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना अंचल के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

परियोजना से जिले की 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है। इससे 338 गांवों के 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहां माही परियोजना के बांध से 105 कि.मी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा। मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका कार्य नवंबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें 210 डिग्गियां और 4 कि.मी. लम्बी टनल भी बनेगी।

इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है। यह गांगड़ तहसील के लंकाई गांव में स्थित है। यह साइफन परियोजना की एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसमें से मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है।

महारानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 15 जून को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद एवं कैम्प के अवलोकन के बाद लगभग 226 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य में जल्द ही महारानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी तथा विकास होगा। राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवन्ती बाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा था।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री ने कर्नाटक, तमिलनाडु एवं प. बंगाल के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान भवन निर्माण हेतु बेंगलुरू, कोलकाता तथा चेन्नई में उचित स्थान पर 3-3 हजार वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जाए।

श्री गहलोत ने पत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखा है कि आईटी सिटी बेंगलुरू में राजस्थान भवन के निर्माण से शहर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ-साथ राजस्थानी कला एवं संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी आयोजित हो सकेंगी। जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सकेगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र में श्री गहलोत ने लिखा है कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में राजस्थान भवन के निर्माण से शहर में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों एवं यात्रा कर रहे राजस्थानियों को घर से दूर घर जैसा वातावरण मिल सकेगा और वे राजस्थानी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। यह कदम दोनों राज्यों की महान संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और गति प्रदान करेगा।

श्री गहलोत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा है कि चेन्नई में राजस्थान भवन बनने से दोनों राज्यों के बीच एक दूसरे की समृद्ध संस्कृतियों के संपर्क में वृद्धि होगी। चेन्नई में राजस्थान के आगंतुक घर से दूर राजस्थानी आतिथ्य और व्यंजनों का लाभ उठा सकेंगे।

साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की होगी शुरुआत

राज्य सरकार साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार से सुशोभित करेगी। प्रोत्साहन में श्री कन्हैया लाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, डॉ. सीताराम लालस एवं श्री विजयदान देथा के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रक्रिया, मार्गदर्शिका एवं चयन समिति से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

पद्य श्रेणी में श्री कन्हैया लाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य/कला श्रेणी में श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, भाषा/अनुसंधान श्रेणी में डॉ. सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार तथा गद्य श्रेणी में श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर को इन पुरस्कारों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।

पुरस्कार में 11-11 लाख रुपये नकद राशि, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किये जा सकेंगे। सम्मान उन व्यक्तियों, संस्था अथवा संगठन में बांटा जा सकेगा, जिन्हें चयन समिति समान रूप से पात्र समझती है। सभी पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, राजस्थान दिवस अथवा अन्य अवसरों पर प्रदान किए जा सकेंगे।

पुरस्कार चयन के लिए गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार

द्वारा मनोनीत गैर राजकीय व्यक्ति होंगे। पद्मश्री/साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो साहित्यकार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के अध्यक्ष एवं कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति में सदस्य तथा उप शासन सचिव सदस्य सचिव होंगे।

समिति प्राप्त आवेदनों के विचारण के बाद तीन-तीन के समूह में चयनित साहित्यकारों का पैनल बनाकर अनुशंसा सहित अंतिम निर्णय के लिए प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।

नदबई में सेंदपुरा को उप तहसील बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 15 जून को भरतपुर जिले के सीकरी में महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के बाद आयोजित किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया तथा वहां उपस्थित अधिकारियों से योजनाओं की क्रियान्विति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने 165 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नदबई में सेंदपुरा को उप तहसील बनाने तथा नगर क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की।

लोक कला विकास बोर्ड का होगा गठन

लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

बोर्ड गठन का उद्देश्य लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलवाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना, कलाओं का प्रचार-प्रसार, संस्थाओं का पर्यवेक्षण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करना, लोक कलाओं के सम्बन्ध में प्रकाशन, समीक्षा करना, लोक कला मेलों, प्रदर्शनी, व्याख्यानमाला, गोष्ठियों, समारोह का आयोजन करना तथा लोक कलाकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023 को मुख्यमंत्री की स्वीकृति

प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।

अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य (पंजीकृत सक्रिय श्रमिक) को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023 के प्रारूप को सहमति प्रदान की है।

योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मजदूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो डीबीटी से भर्ती की अवधि या 7 दिवस (जो भी कम हो) के लिए प्रतिदिन 200 रुपये की सहायता पहुंचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी।

श्रमिक की अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में भी योजना के तहत सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी

महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, देशभक्ति, दानशीलता, जनसेवा और कर्त्तव्य परायणता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड में सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने उदयपुर में 22 मई को कालजयी योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति में बोर्ड गठित करने की घोषणा की थी।

इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के महान चरित्र का अनुगामी बनाना, उन पर आधारित पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण एवं नव-निर्माण, भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित प्राचीन साहित्य के संकलन, संरक्षण, शोध, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार, संबंधित पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण-समावेशन करना है।

साथ ही, उनके नाम से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की शुरुआत करना, उन पर आधारित मेलों, प्रदर्शनी, समारोह, सम्मेलन, फिल्मों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कवि सम्मेलनों का आयोजन करना एवं देश-विदेश में उनके विचारों का प्रचार-प्रसार का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

4 एडीएम, 3 उपखंड, 12 तहसील तथा 16 उप तहसील कार्यालय खुलेंगे

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4 अतिरिक्त जिला कलक्टर, तीन नवीन उपखंड, एक नवीन तहसील, 11 क्रमोन्नत तहसील व 16 नवीन उप तहसील कार्यालयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन कार्यालयों के संचालन के लिए 406 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा।

इसमें रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), भीनमाल (जालोर), सीकर शहर एवं मालपुरा (टोंक) में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही, रींगस (सीकर), माधोराजपुरा (जयपुर) एवं टपूकड़ा (अलवर) में नए उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे।

वहीं, टोंक के अलीगढ़ में नया तहसील कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही राजलदेसर (चूरू), मांढण एवं प्रतापगढ़ (अलवर), रूदावल (भरतपुर), जुरहरा (भरतपुर), हदा (बीकानेर), बाटाडू (बाड़मेर), भांडारेज (दौसा), जालसू (जयपुर), पिलानी (झुंझुनूं) एवं रायथल (बूंदी) में उप तहसील कार्यालय अब क्रमोन्नत होने पर तहसील कार्यालय के रूप में संचालित होंगे।

इसके अलावा बघेरा (अजमेर), डूंगरा छोटा (बांसवाड़ा), हरसानी (बाड़मेर), ददरेवा (चूरू), बसई एवं नादनपुर (धौलपुर), नारंगदेसर (हनुमानगढ़), रेनवाल मांजी (जयपुर), चंदवाजी (जयपुर), गीजगढ़ (दौसा), बबाई (झुंझुनूं),

कैलादेवी (करौली), लूणवा एवं दीनदारपुरा (नागौर), कल्याणपुर (उदयपुर) तथा रिडमलसर (श्रीगंगानगर) में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से 4 एडीएम कार्यालयों हेतु कुल 40 पद, 3 उपखंड कार्यालयों हेतु 36 पद, एक नवीन तहसील हेतु 25 पद, 11 क्रमोन्नत तहसीलों हेतु 209 पद एवं 16 नवीन उप तहसीलों हेतु 96 पदों सहित कुल 406 पदों का सृजन होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए घोषणा की गई थी।

प्रदेश के 29 महाविद्यालयों में शुरू होंगे नवीन संकाय

राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 29 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों से संबंधित नवीन संकाय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही, नवीन संकायों के लिए आवश्यक नवीन पदों के सृजन एवं वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी प्रदान की है।

प्रदेश के 22 सह-शिक्षा महाविद्यालयों एवं 6 कन्या महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से संबंधित नवीन संकाय खोले जाएंगे। नवीन संकायों के संचालन हेतु सहायक आचार्य के 131, प्रयोगशाला सहायक के 52, प्रयोगशाला वाहक के 52 सहित कुल 235 पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए 33.26 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

साथ ही, उदयपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय, मावली को राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। यहां स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे।

नवीन संकायों के लिए सहायक आचार्य के 10, प्रयोगशाला सहायक के 4, प्रयोगशाला वाहक के 4 पद सहित कुल 18 नवीन पद सृजित होंगे। इसके लिए लगभग 2.55 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी भी दी गई है।

श्री गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा। विद्यार्थियों को अपने पंसदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे।

7 जिलों में खुलेंगी खेल अकादमियां

राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न खेल अकादमियां स्थापित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है।

सीकर के कोलिड़ा एवं बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइक्लिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ (चूरू) में एथलेक्टिस अकादमी तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएंगी। इन अकादमियों का निर्माण 2-2 करोड़ रुपये की लागत से होगा। साथ ही, डीडवाना (नागौर) में कबड्डी अकादमी का निर्माण 25 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

धौलपुर जिले में 643 करोड़ रुपये की लागत से होगा कालीतीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 जून को धौलपुर जिले की जनता को कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास व सिलावट एनिकट परियोजना का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। श्री गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कराने के निर्देश दिए हैं।

बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपये व्यय होंगे। चंबल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। इन बांधों के भरने से जिले की जीवनदायनी बामनी, पार्वती और उटंगन नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इससे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर के 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में जलभराव संभव होगा।

इस परियोजना से धौलपुर जिले के 3 शहरी और 433 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। जिले का भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन व पशुओं के लिए पीने का पानी भी आसानी से सुलभ हो सकेगा।

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव में उटंगन नदी पर 100 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा एनीकट बनाया गया है। इसमें 0.54 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भराव होता है। इस एनीकट के निर्माण से ग्राम सिलावट, जवाहर का पुरा, काटरपुरा और कसियापुरा के गांवों की 12 हजार जनसंख्या को लाभ मिलेगा। साथ ही आसपास के कुंओं, नलकूपों में जलस्तर बढ़ेगा।

25 वर्ष के सेवाकाल पर अब मिलेगी पूरी पेंशन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।

मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय

लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल एल-20 से एल-21 किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी, 2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण 'पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा' किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। श्री शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं।

मंत्रिमंडल में वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्गगज का भूखंड आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। रैगर समाज, बीकानेर को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15,000 वर्गफुट भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से भीलवाड़ा और बीकानेर में गरीब छात्रों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

108 आपातकालीन सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा 104 एवं इससे जुड़ी सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104 को जनहित में आगामी छह माह के लिए अति आवश्यक सेवाएं घोषित किया है।

गृह विभाग द्वारा इस संबंध में 31 मई 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22 की धारा 3 की उपधारा (1) की शक्तियों का उपयोग करते हुए) 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ जननी एक्सप्रेस सेवा 104, चिकित्सा परामर्श सेवा 104 एवं कॉल सेंटर की सेवाओं में हड़ताल किए जाने को आगामी छह माह तक के लिए प्रतिषेध किया गया है। उक्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके परिमाणस्वरूप आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का बढ़ा दायरा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के लिए 31 मई को एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय लिया। इसके तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) में अब 100 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होने के साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट्स प्रतिमाह से अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट्स बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसी प्रकार 200 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के पहले 100 यूनिट्स निःशुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट्स तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य सभी शुल्क भी माफ होंगे। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून, 2023 से दिया जाना है।

रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले शुरू होगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 जून को बाड़मेर के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना की समीक्षा की। 31 दिसंबर 2024 से पहले ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से विकास की गति बढ़ेगी। वर्ष 2013 में यह 37,229 करोड़ रुपये, वर्ष 2017 में 43129 और अब 72937 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना हो गई है।

खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को मिलेगा स्पेशल इन्क्रीमेंट

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिकों को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। 1 अप्रैल, 2023 एवं इसके पश्चात् पात्र कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट के लिए खेल आयोजन के पूर्णता की दिनांक से 6 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

कार्मिकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने (पदक जीतने) पर क्रमशः 1 एवं 2 स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दिए जाएंगे। कार्मिक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 स्पेशल इन्क्रीमेंट ही मिलेंगे। स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ खेल प्रतियोगिता की समाप्ति वाले माह के अगले माह की प्रथम दिनांक से देय होगा।

राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे आर-केट केंद्र

प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 25.90 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। नए आर-केट केंद्र कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय), उदयपुर के विज्ञान भवन (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), भरतपुर के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विभाग (राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय), अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा बीकानेर के स्कूल इनोवेशन हब (महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय) में खोले जाएंगे।

इस निर्णय से युवाओं को ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि की एडवांस्ड तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इन केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जयपुर में भी आर-केट स्थापित किया गया है। साथ ही, जोधपुर के राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर-केट के कोर्स प्रारंभ किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने बढ़ाई होमगार्ड्स के अनुबंध नवीनीकरण की समयावधि

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वालेन्टियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनुबंध नवीनीकरण (कॉन्ट्रेक्ट रिन्यूवल) अवधि को 5 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की घोषणा की है। होमगार्ड्स के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयंसेवकों को लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा रही है।

गोडवाड़ देसुरी-पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व होगा विकसित

राज्य सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली के गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने तथा सिरोही के संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इन कार्यों के लिए लगभग 5.15 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। गोडवाड़ देसुरी में 2 करोड़ रुपये की लागत से लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किए जाने के कार्य होंगे। साथ ही, संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा में 3.15 करोड़ रुपये की लागत से विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन कार्यों के लिए घोषणा की गई थी।

प्रदेश के वन क्षेत्रों में रोमांचकारी गतिविधियां होंगी शुरू

युवाओं को वन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए वन क्षेत्रों में हाईकिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9.74 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इस राशि से प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न वन क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इनमें अजमेर के तारागढ़, अलवर के चूहड़सिद्ध, बारां के रामगढ़ क्रेटर, भरतपुर के ब्रज चौरासी क्षेत्र, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ व मंगरोप, चित्तौड़गढ़ के हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल, दौसा के मेढ़ा व गोलमेल, जयपुर के बुचारा व कचरावाला, सिरोही के मातरमाता, सीकर के बोलेश्वर, प्रतापगढ़ के धूणीमाता व कमलेश्वर महादेव तथा उदयपुर के नाल सांडोल क्षेत्र शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जालोर और पाली में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 20 जून को जालोर में बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री गहलोत ने जालोर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की तथा अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में जानकारी भी ली। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने जालोर के आईपुरा, वेडिया तथा आस-पास के क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को नियमानुसार आपदा राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 21 जून को पाली जिले में बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने पाली सर्किट हाउस में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। श्री गहलोत ने सभी की आत्मीयता से समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित राहत पहुंचाने व सर्वे कराकर नियमानुसार मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। श्री गहलोत को प्रभावितों ने अपने नुकसान के बारे में बताया। साथ ही, उन्होंने प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना की। प्रभावित लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा समय रहते की गई पूर्व तैयारियों से भी नुकसान कम हुआ है। बचाव एवं राहत कार्यों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य स्वयंसेवकों ने दिन-रात काम किया।

कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा

कोटा के राजीव गांधी नगर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। इससे विद्यार्थी और आमजन दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका व खगोलीय घटनाओं के रहस्य आकर्षक मॉडल्स एवं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझेंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। केंद्र में विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सरलता से समझाने के लिए फन साइंस एवं थीमेटिक गैलरीज का निर्माण होगा। आउटडोर एवं इंडोर मॉडल्स की स्थापना होगी तथा भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी।

यहां 80 से 85 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। इसमें विभिन्न खगोलीय ग्रहों की जानकारी उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रोचकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। एक ऑडिटोरियम भी बनेगा, जिसमें 3-डी शो होंगे।

बांसवाड़ा में नवीन उप तहसील छोटी सरवा का गठन

प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिले में नवीन उप

तहसील छोटी सरवा का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से आमजन को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में राहत मिलेगी। नवीन उप तहसील छोटी सरवा में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 12 पटवार मण्डल शामिल होंगे।

जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय

राज्य के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। निदेशालय हेतु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य का एक नवीन पद सृजित किया जाएगा। निदेशालय के मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं डिजाइन एक्सपर्ट के कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेंगी। निदेशालय का मुख्य कार्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना होगा। यह निदेशालय राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। जिसके परिणामस्वरूप राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि होगी। साथ ही, निदेशालय हस्तशिल्प नीति-2022 के अनुसार विभिन्न कार्यों को सम्पादित करेगा।

राज्य के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है।

राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों पर फोकस करते हुए टीबी मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया में वर्ष भर मिशन मोड में विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई। जनप्रतिनिधिगणों, शिक्षकों, टीबी उपचारित रोगियों, टीबी चैम्पियन, स्वास्थ्यकर्मियों, आशा सहयोगिनियों व स्वास्थ्य मित्र कार्यकर्ताओं आदि के समूह गठित किये गये। इन समूहों ने सराहनीय कार्य करते हुए व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही ग्राम पंचायत के टीबी रोगियों को जांच व उपचार-परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करवायी, साथ ही निक्षय पोषण योजना के अतिरिक्त पौष्टिक आहार निक्षय मित्रो ने लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये।

ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्धेश्य से प्रदेश की 1,440 पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया गया जिनमें से 29 ग्राम पंचायतों ने निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। टीबी मुक्त की गई पंचायतों में अलवर जिले की पहल, कुंडला, दुबी, चुरू जिले की डाधर, साहू, डोकवा, वार्ड नंबर 8, कानूता, गुड़ावाड़ी, वार्ड नंबर 17, जांडवा, कुसुमदेसर, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 9 और भैंसाली, हनुमानगढ़ जिले की झंडा वाला सीखा और बेहरवाला पंचायत, जैसलमेर जिले की मांडवा और बादली, झुंझनूं जिले की बुढाना, संजय नगर, वार्ड 13 और चवासरी पंचायत, सीकर जिले की ढाणी गुमान सिंह, मलिकपुर, मावंडा खुर्द और चौनपुरा तथा बूंदी जिले के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 शामिल है।

ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने हेतु सहयोगी एजेंसी आई.ए.पी.एस.एम. ने सघन जांच एवं निरीक्षण कार्य हेतु विभिन्न दल गठित किए और इंसिडेंस (रोगी भार) दर 44 प्रति लाख से कम, प्रेवलेंस (रोग प्रसार) दर 65 प्रति लाख से कम, मृत्यु दर 3 प्रति लाख से कम इत्यादि निर्धारित मापदंड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की कार्यवाही की गई है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित होगा संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत पीपाजी के नाम पर उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही, अध्ययन केंद्र हेतु सह आचार्य का एक पद सृजित किया जाएगा।

श्री गहलोत के इस निर्णय से अध्ययन केंद्र में विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी के विद्यार्थी अध्ययन एवं शोध कर सकेंगे। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

पशुपालकों और गृहणियों को मिली बड़ी राहत

■ टीम सुजस

पशुपालकों के खातों में डीबीटी से भेजे 175 करोड़ रुपये
14 लाख लाभार्थियों के खाते में 60 करोड़ की गैस सब्सिडी हस्तांतरित

राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं किसानों को अधिकतम राहत देने का संकल्प साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 जून को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में करीब 41 हजार 900 पशुपालकों के खाते में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि हस्तांतरित की। लंपी महामारी में दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई थी। इसके क्रियान्वयन में प्रदेशभर के पशुपालकों के खातों में प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपये डीबीटी द्वारा भेजे गये।

इस वर्ष लम्पी महामारी से बचाव हेतु 68 लाख से अधिक गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है।

नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक गौशालाओं को लगभग 2,500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया चुका है। राज्य सरकार के निर्णयों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है।

राज्य सरकार बचत, राहत, बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है। राज्य सरकार जनता पर मंहगाई का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को बढ़ती कीमतों के कारण गैस सिलेंडर खरीदने में कठिनाई हो रही है। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार 1140 रुपये तक का सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करा रही है और आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए किए गए वादे पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव में बटन दबाकर एक साथ इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रूपये के लाभ का हस्तातंरण किया। प्रदेश में महिलाओं को मुखिया बनाकर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू

इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी राशि की पहली किश्त का हस्तांतरण

की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से जनता का पैसा राहत के रूप में जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार की इन योजनाओं से जो बचत होगी, उसे लाभार्थी परिवार अपने बच्चों के भविष्य को संवारने, उनकी पढ़ाई तथा अन्य भरण.पोषण पर खर्च कर सकेंगे।

प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क, 200 यूनिट बिजली तक सभी सरचार्ज हटाने एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

राज्य सरकार के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सभी 33 जिलों में लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण

मुख्यमंत्री ने लाभार्थी उत्सव के दौरान अजमेर के 54694, अलवर के 59514, बांसवाड़ा के 25615, बारां के 29246, बाड़मेर के 67362, भरतपुर के 58515, भीलवाड़ा के 52064, बीकानेर के 5462, बूंदी के 26613, चित्तौड़गढ़ के 41445, चूरू के 56618, दौसा के 41532, धौलपुर के 25918, डूंगरपुर के 19718, हनुमानगढ़ के 36979, जयपुर के 80100, जैसलमेर के 17584, जालोर के 38115 तथा झालावाड़ के 39115 उपभोक्ताओं के खातों में लाभ हस्तांतरित किया।

श्री गहलोत ने झुन्झुनूं के 47181, जोधपुर के 65767, करौली के 28460, कोटा के 27509, नागौर के 70517, पाली के 40731, प्रतापगढ़ के 15005, राजसमंद के 27873, सवाई माधोपुर के 26499, सीकर के 61153, सिरोही के 18817, श्रीगंगानगर के 45200, टोंक के 38950 और उदयपुर के 51553 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण किया।

लाभार्थियों से संवाद के दौरान श्री गहलोत ने उनसे महंगाई राहत कैंपों में मिल रहे लाभ एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जरूरतमंदों को बिना किसी तकलीफ के योजनाओं का लाभ देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया। भीलवाड़ा जिले की निवासी लाभार्थी श्रीमती सुनीता कोली ने खाते में सब्सिडी की राशि आने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू कर राज्य सरकार ने गरीबों के लिये बहुत अच्छा कार्य किया है।

भीलवाड़ा जिले की ही निवासी श्रीमती असमा बानो ने बताया कि वे बीड़ी बनाकर अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं। महंगा होने की वजह से वे पहले गैस सिलेंडर खरीद नहीं पाती थीं। अब वे आसानी से इसे खरीद पाएंगी।

झालावाड़ निवासी श्रीमती ममता सुमन ने बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है और घर में वे अकेली कमाने वाली सदस्य हैं। उनके दो बच्चे हैंए जिनमें से एक दिव्यांग है। गैस सिलेंडर सस्ता होने से उन्हें बहुत लाभ मिला है। इससे जो बचत होगी उससे वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगी।

झालावाड़ की ही लाभार्थी श्रीमती हेमलता ने बताया कि उनके पति का निधन कोरोना से हो चुका है। उनके बच्चे की किडनी खराब है, जिसका इलाज चिरंजीवी योजना से निःशुल्क हो रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं अन्य योजनाओं से आर्थिक सम्बल मिल रहा है।

सिरोही जिले की निवासी श्रीमती भावना कुमारी ने बताया कि उन्हें महंगाई राहत कैम्प में 6 योजनाओं का लाभ मिला है। विशेष रूप से इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का लाभ मिलने से वे बहुत खुश हैं।

66वें नेशनल स्कूल गेम्स

राजस्थान के खिलाड़ियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान

■ मनमोहन हर्ष
उप निदेशक, जनसंपर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खेलकूद गतिविधियों के विकास की दिशा में लिए गए नीतिगत निर्णयों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों से खेलों की आबोहवा में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में खेलों के प्रति लगाव की एक ऐसी संस्कृति पनप रही है, जिसमें न केवल युवाओं का गेम्स के प्रति रुझान बढ़ रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी अपनी पदकीय सफलताओं से प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के बैनर तले भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम, ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया खेल परिसर और नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक साथ आयोजित 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य पदक जीत कर प्रदेश को मालामाल कर दिया। एक और जहां बैडमिंटन, कबड्डी, लॉन टेनिस, हॉकी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और वॉलीबॉल की टीम स्पर्धाओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया, वहीं शतरंज, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, डिस्कस थ्रो और रेसवॉक जैसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी सोने, चांदी और कांसे के तमगे जीतकर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए।

ऐतिहासिक कदमों से संवरी खेलों की सूरत

राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर 50 लाख रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक पर पहले मिलने वाली 30 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार एशियाई और कॉमन वेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपये के स्थान पर 60 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपये की इनामी राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने के राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई गई है, वहीं खिलाड़ियों के अभ्यास और उनकी खेल जरूरतों की देखभाल के लिए हाई परफोर्मेंस स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम जैसी

उच्चस्तरीय खेल सुविधाओं के सृजन की नायाब पहल की गई है। नए खेल मैदान, नई खेल अकादमियां और खेल संस्थानों के विकास के साथ ही राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर पहले से विद्यमान स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और खेल मैदानों को समय की आवश्यकता के अनुरूप अपग्रेड करते हुए सुविधाओं का निरंतर विकास भी किया जा रहा है। इसके अलावा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स की तर्ज पर राज्य गेम्स और राज्य गेम्स की तर्ज पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय खेलों के आयोजन की सोच, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन, राज्य एवं जिला स्तर पर सभी प्रमुख खेलों में युवाओं को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों (कोच) की नियुक्ति और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी जैसे अनेक 'स्पोर्ट्स फ्रेंडली इनिशिएटिव्स' खेलों में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने की दूरगामी सोच के साथ उठाए गए हैं। नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों की सफलता को इन नीतिगत निर्णयों से प्रदेश में खेलकूद और खिलाड़ियों के लिए बने माहौल को देखा जा सकता है।

गोल्ड से बढ़ाया प्रदेश का गौरव

देश में तीन स्थानों पर आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत में नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए भारोत्तोलन मुकाबलों में चायनान पब्लिक स्कूल, बीकानेर के विद्यार्थी केशव बिस्सा ने वेटलिफ्टिंग की हैवीवेट कैटेगरी (102

किलोग्राम से अधिक भारवर्ग) में कुल 288 किलोग्राम भार उठाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। केशव ने क्लीन एंड जर्क में 156 किलोग्राम तथा स्नेच में 132 किलोग्राम भार उठाकर प्रतियोगिता में न केवल स्वर्ण पदक राजस्थान के नाम किया, बल्कि प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का खिताब भी अपने नाम किया। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक्स स्पर्धाओं में नागौर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हीरावति (लाडनूं) की कविता डूडी ने 3,000 मीटर रेसवॉक, चूरू जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ की नीतू कुमारी ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। भोपाल में ही एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो इवेंट में चूरू के सुमित कुमार (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़, चूरू) ने 57.92 मीटर तक तश्तरी फेंककर स्वर्ण पदक जीता। जयपुर की ताश्री मेनारिया (मधु बाल निकेतन, मानसरोवर, जयपुर) ने हैवीवेट बॉक्सिंग (81 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग) में तथा भीलवाड़ा की माया माली (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, भीलवाड़ा) ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते। इन छह स्वर्ण पदकों के अलावा राजस्थान ने दो गोल्ड शतरंज की बिसात पर उदयपुर के प्रणय चौरडिया (द स्टडी सीनियर सेकंडरी स्कूल, बाड़ी, उदयपुर) एवं बीकानेर की युक्ति हर्ष (राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हर्षों का चौक, बीकानेर) के व्यक्तिगत प्रयासों से जीते। उल्लेखनीय है राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में 'नो बैग डे' और 'चैस इन स्कूल' एक्टिविटीज जैसे नवाचार लागू किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती को प्रदेशभर में 'चैस इन स्कूल एक्टिविटी' के तहत सरकारी विद्यालयों के 38 लाख 21 हजार 9 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। नई दिल्ली में स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शतरंज के मुकाबलों में पहली बार शिरकत कर रही राजस्थान की टीम के प्रतिभाशाली सितारों प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष की स्वर्णिम चालों के पीछे स्कूल शिक्षा विभाग के इस नवाचार को एक अहम कारक माना जा सकता है।

रजत पदकों से राजस्थान की चांदी

नई दिल्ली में टेनिस के मुकाबलों में राजस्थान की छात्रा टीम ने इन खेलों में पहली बार फाइनल का सफर तय करते हुए रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। टेनिस में छात्रा टीम की इस सफलता में शामिल जयपुर की सानिया खान (संस्कार स्कूल, सिरसी रोड, जयपुर) ने टेनिस के एकल मुकाबलों में भी रजत पदक जीतते हुए राजस्थान के लिए इन नेशनल गेम्स में दो पदक जीतने की विशेष उपलब्धि अपने नाम की। भीलवाड़ा के विकास विश्नोई (महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा) ने कुश्ती, जयपुर की यामिनी कंवर (राजा रामदेवी पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर, जयपुर) और उदयपुर के आमिल अली (राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर) ने बॉक्सिंग तथा ताइक्वांडो में कोटा की कशिश शक्तावत (आर पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, कोटा) ने भी राजस्थान को रजत पदक दिलाए। इसके अलावा भरतपुर में अंताक्षरी सीनियर सेकंडरी स्कूल के छात्र वीर प्रताप सिंह ने ताइक्वांडो और चूरू में रॉयल प्रिंस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सपना ने कुश्ती के मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीते। जयपुर में जोबनेर स्थित किरण बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोनिया के नरेश चौपड़ा ने 1,500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। वहीं बॉयज की 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में परमेश्वर लाल (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी छापरी, मोलासर, नागौर), तेजसिंह राठौड़ (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा, कोटा), राजपाल जाट (श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा) तथा सौरभ शिवम सिंह (गुरुनानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर) की टीम ने राजस्थान को रजतमयी सफलता से नवाजा।

कांस्य पदक जीत दिखाई करामात

ग्वालियर में खेले गए बैडमिंटन टीम मुकाबलों में वंश शर्मा (संवित शिक्षण सेकंडरी स्कूल), आदित्य राजोरिया (राजकीय विवेकानंद मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल, टोंक), कार्तिक जैन (माई ओवन स्कूल, जयपुर), कुनाल चौधरी (दिल्ली पब्लिक स्कूल) एवं कार्तिकेय (सीनियर सेकंडरी स्कूल, दातारामगढ़) ने प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया, वहीं दिल्ली में छात्रों की कबड्डी टीम ने भी राजस्थान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी प्रकार निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी राजस्थान की छात्रों की टीम ने कांस्य पदक जीता। भोपाल में जूडो की 45 किलोग्राम कैटेगरी में कोटा में राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल के धर्मा मारू ने छात्र वर्ग और छात्रा वर्ग में श्रीगंगानगर के गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल की लावण्या अरोड़ा और भीलवाड़ा की गवर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल की नेहा चौधरी ने प्रदेश के लिए कांस्य पदक जीता। हेमर थ्रो स्पर्धा में चूरू के आकाश (राजकीय विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिद्धमुख, चुरू), कुश्ती में भरतपुर के मोहन (हरि आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमदपुर, डीग), बॉक्सिंग में जोधपुर के संकल्प लवानिया (श्री केके मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर), जोधपुर के रितिक सिवाच (वंदना पब्लिक अकादमी, प्रताप नगर, जोधपुर) एवं जोधपुर के ही अमन घिटेला (न्यू सेंट्रल अकादमी, जोधपुर) तथा भारोत्तोलन में अलवर की सलोनी सैनी (राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर), ताइक्वांडो में जयपुर के जनक सोनी (जयश्री पेरिवाल ग्लोबल स्कूल, जगतुपरा) ने कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। भोपाल में राजस्थान की 4 गुणा 400 रिले टीम ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। •

कृषि में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा बढ़ोतरी

कृषि शिक्षा में
छात्राओं का बढ़ रहा रुझान

■ अभिषेक चतुर्वेदी

कृषि क्षेत्र में बुवाई से लेकर रोपण, सिंचाई, कटाई और भंडारण जैसे कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023-24 में 'राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन' की शुरुआत की है। इसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गई है।

इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक मिल रही 5 हजार से 15 हजार की राशि को बढ़ाकर अब 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी।

कृषि संकाय चुनने पर प्रोत्साहन

मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मिशन से 84 हजार 583 छात्राएं लाभान्वित

इस मिशन के तहत गत 4 वर्षों में (17 दिसंबर 2018 से मार्च 2023 तक) अध्ययनरत 84 हजार 583 छात्राओं को कुल 55 करोड़ 17 लाख 87 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है। जिसमें वर्ष 2018-19 में 11 हजार 605 छात्राओं को 7 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये का आर्थिक संबल दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 15 हजार 780 छात्राओं को 9 करोड़ 30 लाख 6 हजार रुपये का, वर्ष 2020-21 में 14647 छात्राओं को 10 करोड़ 75 लाख 23 हजार रुपये का, वर्ष 2021-22 में 20 हजार 867 छात्राओं को 12 करोड़ 84 लाख 56 हजार का रुपये प्रोत्साहन देकर लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में 21 हजार 684 छात्राओं को 14 करोड़ 40 लाख 33 हजार रुपये का आर्थिक संबल दे कर कृषि संकाय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बढ़ते हुए आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की यह मुहिम छात्राओं को कृषि संकाय चुनने के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इससे न केवल छात्राएं कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं बल्कि देश में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

पात्रता

मिशन में आवेदन करने के लिए छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

कृषि संकाय चुनने पर दिव्या और कंचन को मिला संबल

कृषि संकाय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रही दिव्या गुर्जर, जोबनेर, जयपुर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। योजना के तहत उसे बीएससी के चारों वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इसके बाद एमएससी में कृषि संकाय में प्रवेश लेने के बाद भी उन्हें दोनों वर्ष 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

वे बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की इच्छा थी। वे चाहती थीं कि वे कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के बारे में जानें और उनके उपयोग से अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग करें। दिव्या कहती हैं कि वे पढ़ाई के साथ-साथ किसानों को खेती करने की उन्नत तकनीकों, बीज, उर्वरक जैसी सहायक सामग्रियों के बारे में उचित जानकारी भी देती हैं।

इसी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीएससी चतुर्थ वर्ष की छात्रा कंचन गंगानी भी इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहती हैं कि इस योजना के कारण उन्हें कृषि विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है। वे चाहती हैं कि वे कृषि की नवीनतम तकनीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें और इस क्षेत्र में कोई नवाचार करें। कंचन बताती हैं कि उनके घर में पहले सब्जियां बाजार से खरीद कर लाते थे लेकिन अब वे घर में सब्जियां उगाती हैं, जिससे उन्हें घर में ही ताजी सब्जियां उपलब्ध होती हैं।

दादर धाम

दादर धाम, जयपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर जयरामपुरा गांव में स्थित है। यह स्थान दादू पंथ के प्रवर्तक श्री दादू दयाल के शिष्य श्री जगजीवन की तपोस्थली है। गुफा के अलावा यहां दादू दयाल मंदिर, शिवालय और एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। दादू दयाल मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। बरसात के दिनों में पहाड़ी पर हरियाली होने से यहां मनमोहक दृश्य बन जाता है। जयपुर के नजदीक होने से यहां श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं।

आलेख और छाया: अशोक गुरावा
मुख्य फोटो अधिकारी

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

तब

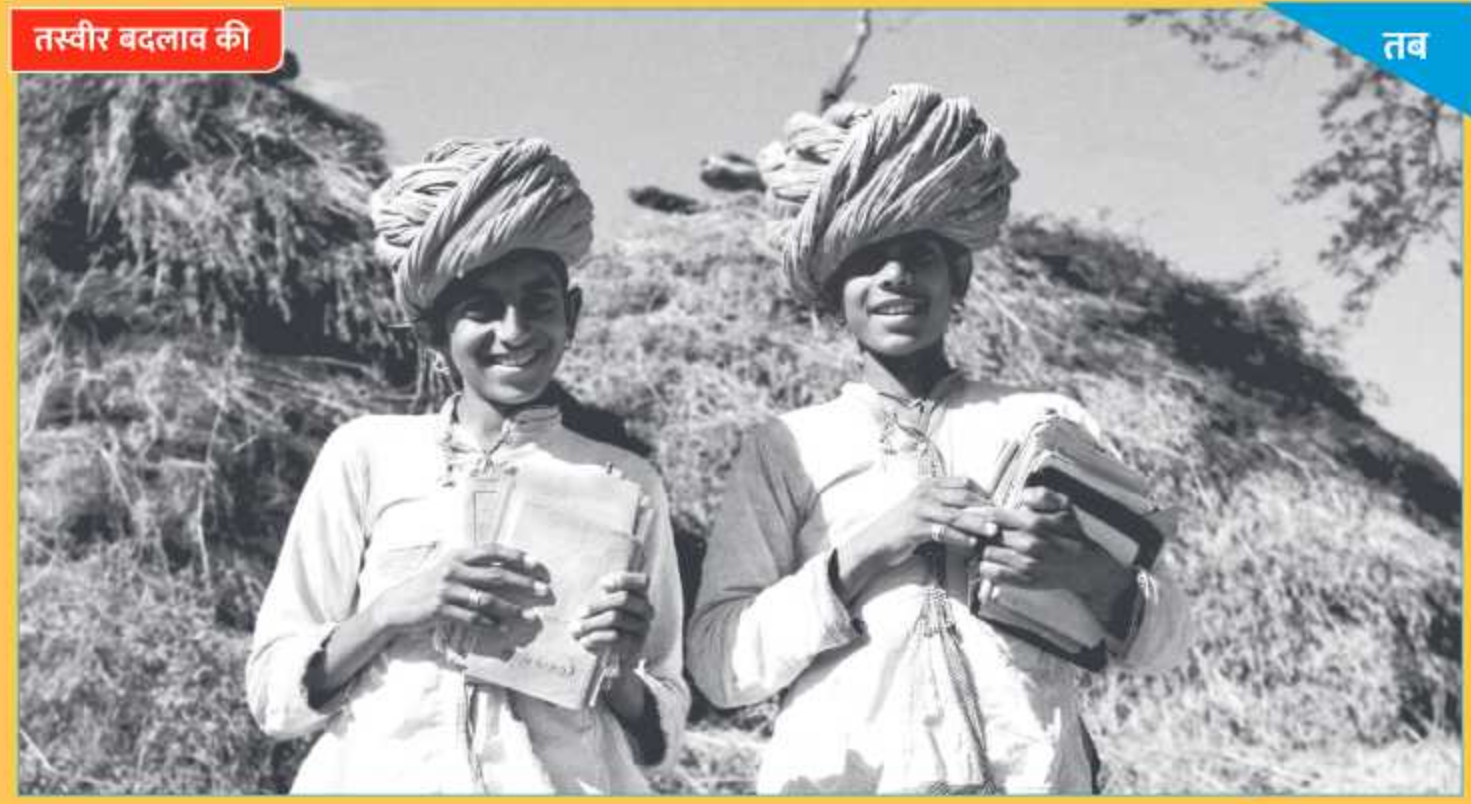

अब

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

@DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
संपादक - श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, 12 रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 33.30 रुपये • 1,00,000 प्रतियां